कृषि विश्लेषण जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2081, जून 2024

नई सरकार
अपेक्षाएं और चुनौतियां

प्रांतीय विचार वर्ग

सचित्र झलक

गुजरात

दुर्ग, छत्तीसगढ़

महाकौशल

मध्य भारत

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–32, अंक–6

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2081 जून 2024

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

आगामी बजट से अपेक्षाएं

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **आवरण कथा**
शासन की नई वास्तविकताएं .... के.के. श्रीवास्तव

10 **आवरण कथा**
नई सरकार, पर अपेक्षा वही .... अनिल जवलेकर

12 **बहस**
क्या–क्या बदलने वाला है इस चुनाव परिणाम के बाद? .... विक्रम उपाध्याय

14 **विश्लेषण**
''पड़ोसी पहले और सागर दृष्टिकोण'' वाली नीति को तवज्जो .... शिवनंदन लाल

16 **मुद्दा**
सतत विकास के लिए रचनात्मक और नवाचार .... डॉ. धनपतराम अग्रवाल

18 **आर्थिकी विमर्श**
अर्थव्यवस्था में आगे भी मजबूती के संकेत .... अनिल तिवारी

20 **समीक्षा**
मोदी सरकार में विज्ञान की प्रगति .... डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

22 **विमर्श**
विपक्ष की मुफ़्त की गारंटियों के बावजूद एनडीए को बहुमत .... स्वदेशी संवाद

24 **विचार**
क्या भारत कभी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? .... प्रहलाद सबनानी

26 **कृषि**
कृषि बजट वृद्धि दिलाएगी 'अरबपति राज' से मुक्ति .... देविन्दर शर्मा

28 **आजकल**
सोना क्यों बन रहा है पहली पसंद? .... स्वदेशी संवाद

30 **यात्रा वृतांत**
भारत के बाहर भारतीयता .... विनोद जौहरी

32 **जल प्रबंधन**
जल संकट: जल के छल का कैसे हो हल? .... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

34 **दृष्टिकोण**
आरक्षण की चिंगारी बन गई दावानल? .... डॉ बालाराम परमार 'हँसमुख

पाठकनामा

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता

भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जोहो ने 200 मिलियन डॉलर का निवेश करके तमिलनाडु में सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए स्कॉटलैंड स्थित क्लास–सिक में प्रौद्योगिकी का लाइसेंस लेने की योजना है।

उनकी यह योजना सरकार की उस स्कीम का नतीजा है जिसमें वह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण की योजना शुरू करने के अंतर्गत कंपनियों को कई तरह के लाभ देती है। सरकार ने जून 2023 में सेमीकंडक्टर के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कंपनियों को पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत के बराबर राजकोषीय प्रोत्साहन देने की योजना कुछ शर्तों के साथ बना रखी है।

जोहो के अलावा अभी भारत में टाटा समूह ने 91 हजार करोड रुपए के निवेश के साथ अपना पहला मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में शुरू कर रहा है।

वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर के मामले में अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश भी ताइवान और चीन पर निर्भर है लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू होने से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता तो कम होगी ही और विश्व में भारत का कद भी बढ़ेगा।

विजित कुमार, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

हम सब मिलकर 'विकसित भारत 2047' के इरादे के साथ 'राष्ट्र प्रथम' के लक्ष्य को हासिल करेंगे।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े परिवर्तनकारी बदलावों की राह के एक ऐसे मोड़ पर है, जो अधिक स्थिरता और विकास लाएगी।

शशिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

भारत का फैसला स्थिरता और निरंतरता के लिए है। मौजूदा सरकार की नीतियों ने आर्थिक विकास के साथ–साथ तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया है।

अजय चौधरी, सह–संस्थापक, एच.सी.एल.

हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत की विकास दर साल दर साल कैसे तेज होती जा रही है और खास तौर पर 2020–21 के बाद अर्थव्यवस्था में क्या बुनियादी बदलाव हुए हैं? हमें यह भी समझना होगा कि वर्ष 2023–24 में विकास की उच्च दर के मुख्य चालक क्या हैं।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में बदलाव का मामला

मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति ऋण नियंत्रण के मात्रात्मक और चयनात्मक उपायों से संबंधित है, जिसमें ब्याज की नीतिगत दरें, खुले बाजार संचालन, नकद आरक्षित अनुपात में बदलाव और अन्य शामिल हैं। पूरी दुनिया में ब्याज की नीतिगत दरें मौद्रिक नीति संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के बारे में अपनी धारणा और अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग और आपूर्ति के आधार पर नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा करता है। इस मामले में आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को अपनी सीमा से बाहर जाने से रोकना होता है। 2017 से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के रुख के बारे में अपनी धारणा निर्धारित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग कर रहा था। 2014 में, तत्कालीन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए डब्ल्यूपीआई के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का उपयोग करने की सिफारिश की थी।

27 जून 2016 को, एमपीसी पहली बार अस्तित्व में आई। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं और तीन भारत सरकार द्वारा नामित बाहरी सदस्य होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एमपीसी देश के लिए मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। आरबीआई गवर्नर के साथ बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास वोट देने का अधिकार होता है। समिति का वर्तमान अधिदेश 31 मार्च 2026 तक 4 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति को बनाए रखना है, जिसमें 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता और 2 प्रतिशत की निचली सहनशीलता है।

पिछले वित्तीय वर्ष में, हालांकि सीपीआई प्रतिशत उच्च रहा, जबकि डब्ल्यूपीआई नकारात्मक क्षेत्र में रहा। लेकिन एमपीसी शासनादेश के कारण सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण जारी रखा, और इसलिए, नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण, एमपीसी ने बहुत कम या यहां तक कि नकारात्मक डब्ल्यूपीआई के बावजूद, जनवरी 2023 से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर ही रखा है। यह कोई रहस्य नहीं है कि नीतिगत ब्याज दरें, विशेष रूप से रेपो दर अर्थव्यवस्था में विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि ब्याज की कम दर निवेश और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और घरों की खरीद को प्रोत्साहित करती है। यदि ब्याज दर उच्च बनी रहती है, तो अधिशेष धन वाले लोग ब्याज वाले बॉन्ड रखने की कोशिश करेंगे और अचल संपत्तियों में निवेश नहीं करेंगे। साथ ही, जिन लोगों को निवेश और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और घरों की खरीद के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, वे ऐसा करने के लिए कम इच्छुक होंगे। इसलिए मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के नाम पर, वास्तव में विकास पर अंकुश लग जाएगा।

कई अर्थशास्त्रियों ने अब सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना भी महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता मुद्रास्फीति से परेशान न हो, क्योंकि इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर पड़ता है। लेकिन मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, उसके आधार के रूप में सीपीआई या यहां तक कि डब्ल्यूपीआई के भी औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, वे निम्नलिखित तर्कों पर अपना पक्ष रखते हैंः सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का विचार पश्चिम से आयातित विचार है। हम समझते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में विकास, रोजगार और गरीबों और वंचितों का उत्थान शामिल है। इन उद्देश्यों को संबोधित किए बिना कोई भी मौद्रिक नीति पूरी नहीं होती है। दूसरे, अगर हम देखें तो ऐसे कई मौके आए हैं, जब एमपीसी द्वारा सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का पूरी तरह से पालन करने के बावजूद, मुद्रास्फीति न केवल नियंत्रित नहीं हुई, बल्कि कई मौकों पर 6 प्रतिशत के स्तर को भी पार कर गई। यह इस तथ्य को साबित करता है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई की तुलना में सही आधार नहीं है। हम समझते हैं कि सीपीआई खाद्य कीमतों से काफी प्रभावित होता है। खाद्य कीमतें मौसमी कारकों के कारण अधिक बढ़ती हैं और आम तौर पर अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों से नहीं। ऐसा लगता है कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण आईएमएफ का एजेंडा है, जबकि दुनिया अभी भी इस बात पर बहस कर रही है कि हमें सीपीआई या डब्ल्यूपीआई का उपयोग करना चाहिए, आईएमएफ ने न केवल मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की अनिवार्यता के बारे में, बल्कि विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के लिए सीपीआई का उपयोग करने के बारे में भी ज़ोर दिया है। इस पर आपत्ति किया जाना स्वाभाविक ही है। सबसे पहले, हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या केवल मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ही काम करेगा या हमें मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्यों के बारे में भी सोचना होगा।

हालांकि, हम देखते हैं कि 2021–22 और 2023–24 के बीच की इस अवधि के दौरान, डब्ल्यूपीआई सीपीआई से बहुत कम रहा। हालांकि, चूंकि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सीपीआई को एंकर के रूप में उपयोग कर रही थी, और ब्याज की नीतिगत दरें लगातार बढ़ती रहीं, इसने अब डब्ल्यूपीआई को नकारात्मक क्षेत्र में ले जाकर विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इससे देश में अपस्फीति की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उत्पादकों की उत्पादन बढ़ाने में रुचि कम हो सकती है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ नहीं है। इसलिए, यह समय रुक कर समझने और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए एंकर को बदलने के बारे में सोचने का है। याद रखें, आर्थिक नीतियाँ, चाहे राजकोषीय हों या मौद्रिक, सीधी रेखा में नहीं चल सकतीं। आर्थिक नीतियों के बारे में निर्णय लेने से पहले हमें वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को समझना चाहिए।

आगामी बजट से अपेक्षाएं

हालांकि, अंतरिम बजट फरवरी 2024 में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था, अब जुलाई 2024 में पूर्ण केंद्रीय बजट 2024–25 पेश करने का समय आ गया है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों के साथ तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अर्थशास्त्री, किसान, एनबीएफसी, बाजार विशेषज्ञ और कई अन्य शामिल हैं।

19 जून को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आगामी बजट के बारे में अपना दृष्टिकोण देने के लिए आमंत्रित किया गया। सरकारी हलकों में लोग 8.2 प्रतिशत की उच्च जीडीपी वृद्धि, 9.9 प्रतिशत की तेजी से बढ़ते विनिर्माण, अप्रैल 2024 में सीपीआई मुद्रास्फीति के 4.82 प्रतिशत के साथ मुद्रास्फीति में कमी, डब्ल्यूपीआई में कमी, राजकोषीय घाटे के बजट अनुमानों से कम रहने, रुपये में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.4 प्रतिशत की बहुत कम दर गिरावट, और भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता घाटा जीडीपी के बमुश्किल 0.7 प्रतिशत रहने को लेकर उत्साहित हैं। 2023–24 में, जून के पहले सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार 665.8 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, और जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है।

अब मोदी 3.0 के सामने चुनौती इस वृद्धि को बनाए रखने के साथ–साथ मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने की है। बैठक में मौजूद सभी अर्थशास्त्री सरकार की राजकोषीय समझदारी, विनिर्माण संवृद्धि और बीओपी मुद्दों से निपटने की सराहना कर रहे थे। राजकोषीय समझदारी से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक पूर्व शर्त है। कम राजकोषीय घाटे को जारी रखने के बारे में आम सहमति थी। चूंकि सरकार ने पहले ही अंतरिम बजट 2024–25 में जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव रखा है, इसलिए सरकार के लिए इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं है।

मोदी 3.0 के सामने चुनौती जीडीपी वृद्धि को बनाए रखने के साथ–साथ मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने की है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके कारण सरकार को पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे के लिए अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च; पीएलआई योजना, विशेष रूप से नए क्षेत्रों में उसके विस्तार के साथ। इसके अलावा, बेरोजगारी की समस्या, विशेष रूप से शिक्षित युवा बेरोजगारी को संबोधित करने की भी तत्काल आवश्यकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोजगारः रोबोट टैक्स का सुझाव

बैठक में मौजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने नई तकनीक, खास तौर पर एआई के कारण नौकरियों के नुकसान के बारे में चिंता जताई और अन्य लोगों ने भी उनसे सहमति जताई। एक राय यह थी कि हालांकि, हम नई तकनीक के उपयोग से बच नहीं सकते और न ही

बचना चाहिए, लेकिन चूंकि इससे नौकरियां जा रही हैं, इसलिए जो लोग लाभ उठा रहे हैं, उन्हें नुकसान उठाने वालों, यानी वे कर्मचारी जिनकी नौकरियां जा रही हैं या नौकरी के बाजार में नए प्रवेशकर्ता, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, की भरपाई करनी चाहिए।

रोजगार सृजन पर हमले का जिक्र करते हुए, यह सुझाव दिया गया कि 'रोबोट टैक्स' की संभावना तलाशी जा सकती है, जिसका उपयोग विस्थापित श्रमिकों को पुनः कौशल प्रदान करने और पुनर्वासित करने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि हाल ही में आई एम इफ़ द्वारा एक पेपर में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि एआई समग्र रोजगार और मजदूरी को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन तर्क दिया गया है कि यह "श्रम बल के बड़े हिस्से को लंबे समय तक काम से बाहर रख सकता है, जो एक दर्दनाक संक्रमण की ओर इंगित करता है।"

एमएसएमआई के लिए डिज़ाइन किया जाये पीएलआई

पीएलआई योजना के पहले चरण की सफलता से उत्साहित, जिसने एपीआई, रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य में चीन पर निर्भरता को कम करने में मदद की, अर्थशास्त्रियों ने पीएलआई के अगले चरण को सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) के इर्द–गिर्द डिज़ाइन करने का समर्थन किया। रोज़गार सृजन पर नज़र रखते हुए, अधिक संतुलित औद्योगिक विकास के लिए के लिए पीएलआई योजना को एमएसएमई के लिए डिज़ाइन करना महत्वपूर्ण है।

ई–उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने की तैयारी

यह समझा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क पर रोक समाप्त हो जाएगी। डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने की तैयारी के रूप में, हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल वस्तुओं के लिए भारतीय सीमा शुल्क मैनुअल में विशिष्ट टैरिफ शीर्ष बनाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर शून्य प्रतिशत के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र टैरिफ के साथ डिजिटाइज़ करने योग्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, सपोर्ट या ड्राइवर डेटा और अन्य डिजिटल उत्पाद शामिल हैं। इंडोनेशिया ने पहले ही यह कदम उठा लिया है। इससे डेटा एकत्र करने और 01/04/2026 के बाद उचित दरों पर सीमा शुल्क लगाने में सुविधा होगी, जब विश्व व्यापार संगठन द्वारा ई–ट्रांसमिशन के सीमा शुल्क पर लगाई गई रोक समाप्त हो जाएगी।

निजी निवेश को बढ़ावा देना

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ई–उत्पादों पर टैरिफ लगाने से दीर्घकाल में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित उत्पादों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कई अन्य उद्योगों और स्टार्ट–अप में भी निवेश को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। घरेलू स्रोतों से इस निवेश को वित्तपोषित करने के लिए, हमें घरेलू निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल देने की आवश्यकता है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठक में जिन सुझावों पर चर्चा की गई, उनमें शामिल हैं:

1. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के प्रवाह में घर्षण को दूर करने के लिए सूचीबद्ध, गैर–सूचीबद्ध क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ समानता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। एआईएफ द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के अनुसार कर लगाया जाता है। वर्तमान में सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ आमतौर पर 10 प्रतिशत की दर से और गैर–सूचीबद्ध शेयरों और अन्य परिसंपत्तियों पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है।

2. जैविक रसायन, प्लास्टिक और ईवी से संबंधित उपकरणों सहित चीन से आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना) शुरू की जानी चाहिए।

3. छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए घोषित रक्षा गलियारों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं, कॉमन टूल रूम और आरएंडडी सुविधाओं के साथ औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। उचित लागत पर रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए 'इसरो मॉडल' को अपनाया जा सकता है।

4. हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'रिवर्स फ़िलपिंग' यानि देश में वापस लौटने वालों को अपेक्षित कर का भुगतान करना होगा और अधिकांश 'रिवर्स फ़िलपिंग' करने वाले लोग इसे देने के लिए तैयार भी हैं, फिर भी लालफीताशाही और प्रक्रियाओं और ढेर सारे कागजी काम से जुड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। चूंकि, यह (रिवर्स फ़िलपिंग) एक बार का मामला है, इसलिए सरकार रिवर्स फ़िलपिंग की सुविधा के लिए एक पैकेज ला सकती है और जो लोग वापस लौट रहे हैं उनके लिए असुविधा को कम कर सकती है। यह सभी के लिए लाभ की स्थिति हो सकती है; चाहे वह सरकारी राजस्व हो, स्टार्ट–अप इकोसिस्टम हो या पूरा देश हो।

5. सरकार दीर्घकालिक नवाचार को वित्तपोषित करने के लिए अधीनस्थ तंत्र के रूप में मिश्रित निधि को निधियों के रूप में स्थापित कर सकती है। ❑❑

शासन की नई वास्तविकताएं

कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता चलता है। पूरे 10 साल बाद केंद्र में एक बार फिर गठबंधन सरकार के पक्ष में परिस्थितियां निर्मित हुई है। भाजपा अपने दम पर साधारण बहुमत प्राप्त करने से 32 सीटें कम पर रुक गई है। बावजूद तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यू) के समर्थन से केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर अगले 100 दिनों का लक्ष्य भी तय कर दिया है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर आम चर्चा है कि क्या देश एक बार फिर लगभग तीन दशक पुराने गठबंधन युग की ओर लौट चला है और इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों से देश में चल रही विकासवादी कार्यक्रमों के राह रूकावटो की भी आशंका व्यक्त की जा रही है।

वर्ष 2014 के चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने लायक बहुमत देकर गठबंधन की सरकारों से मुंह मोड़ लिया था। 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर जीता कर जनता ने मजबूत सरकार के लिए सहमति जताई थी। इस बीच विरोधी पार्टियों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते हुए देश भर में यह प्रचारित किया कि भारत की राजनीति एकध्रुवीय दिशा में बढ़ रही है जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

मौजूदा 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों ने जातीय जनगणना और सरकार द्वारा संविधान बदलने की बात को जोर शोर से प्रचारित कर मतदाताओं के एक बड़े तबके को अपने पाले में करने की कोशिश की। चुनाव परिणाम में पूर्व के यूपीए गठबंधन का विस्तारित संस्करण इंडिया ब्लॉक एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आया तथा 235 सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया। इंडिया गठबंधन के बैनर तले 235 सांसद चुनाव जीतने में सफल हुए। इस तरह तीन दशक बाद संसद को एक मजबूत विपक्ष भी मिल गया। अब संसद की राजनीति द्विध्रुवीय हो गई है। मतदाता अपने–अपने हिसाब से दोनों गठबंधनों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव में जिन राजनीतिक दलों ने इन दोनों गठबंधनों से बाहर रहने का विकल्प चुना वे चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल सके। बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल के हाथ से राज्य की राजनीति निकल गई। हालांकि दोनों गठबंधनों के कांटे के संघर्ष के बीच 16 निर्दलीयों ने चुनाव में बजी मार ली है लेकिन ढेर सारे दलों के समक्ष अब आगे अस्तित्व बनाए रखने का संकट भी बढ़ता जा रहा है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना की एक सक्षम सरकार।

– के.के. श्रीवास्तव

वर्ष 2014 का चुनाव अनिवार्य रूप से तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की पृष्ठभूमि में बदलाव के लिए था। 2019 में पुलवामा और बालाकोट के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी और अधिक मजबूत होकर उभरी थी। लेकिन मौजूदा चुनाव सामान्य चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव में भावनात्मक मुद्दे गायब थे। यहां तक की धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा भी मतदाताओं को रिझाने में नाकामयाब रहा। अबकी चुनाव में मतदाताओं ने अपने रोज–रोज की रोजी–रोटी की समस्याओं अत्यंत स्थानीय मुद्दों को आगे रखा। यही कारण है कि आत्मविश्वास से लबालब और चुनाव से 4 महीना पहले ही 400 पार का दावा करने वाली भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और 2019 की तुलना में कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेतृत्व वाले दल के लिए यह तीसरा चुनाव था और अंततोगत्वा राजग गठबंधन सरकार बनाने में भी सफल हुआ।

परिस्थितियां गठबंधन सरकारों के पक्ष में है। 11 राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अच्छी खासी उपस्थिति है। इन राज्यों में 347 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे 10 राज्य हैं जहां स्थानीय पार्टियों का या

तो कभी दबदबा नहीं रहा या फिर उनका पतन हुआ है। इन राज्यों का 169 सीटों पर प्रतिनिधित्व है। यह कुल 21 राज्य मिलकर लोकसभा की 500 से ज्यादा सीटों पर मायने रखते हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन इन जगहों पर बहुत कमजोर था, जिससे भाजपा को बढ़त मिल गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ लगातार मिलकर काम किया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में एकता बनाए रखी। तात्पर्य है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों के बीच महत्वपूर्ण विश्वास नेता हासिल की है और इसे हासिल करने के लिए पर्याप्त संख्या मेंसहयोगी दलों को जगह देने को भी तैयार हुई है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिदृश्य गठबंधन के पक्ष में है।

अब दूसरी तरफ देखें तो अगर टीडीपी और जनता दल (यू) राजग गठबंधन के बचाव में आगे नहीं आए होते तो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने में तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी होती। इसे देखते हुए लगता है कि भाजपा को 10 साल बाद फिर से गठबंधन की राजनीति और समझौतो को अपनाने की नीति स्वीकार करनी होगी। इसी के चलते जाहिर तौर पर हितधारक नौकरशाह वित्तीय बाजारों और अर्थशास्त्रियों के बीच चिंताएं हैं कि अब आगे सुधारों की गति प्रभावित हो सकती है। हालांकि गठबंधन शासन का पिछला रिकॉर्ड (नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेई, मनमोहन सिंह) इसके विपरीत इशारा करता है। यह सभी जानते हैं कि गठबंधन सरकारों का सुधारों को लागू करने का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। सुधार के बहुत सारे बड़े कार्य नरसिंह राव, एचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेई और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए। उनकी सुधारवादी नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को प्रगति के पंख भी लगे। ऐसे में अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नयी एनडीए सरकार कैसे आगे बढ़ती है और उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होगा कि एक मजबूत विपक्ष कितनी जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करता है। हालांकि यह कार्य बहुत आसान नहीं है लेकिन एक युग के लौटने के कारण उम्मीद की जा सकती है।

नई सरकार के बनने के बाद यह माना जा रहा है कि इसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब बहुसंख्यकवादी लाइन पर उस तरह नहीं चल पाएगी जैसे पहले के दो कार्यकालों में चलकर दिखाया था।

संभव है कि गठबंधन के सहयोगी बार–बार अपनी पसंद की चीजों की मांग करें तथा उसके लिए हठ भी कर सकते हैं लेकिन यह भी तय है कि वह अपनी सीमाएं जानते हैं। गठबंधन को टूटने की स्थिति तक वह भी नहीं पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल रोज–रोज महंगा होते जा रहे चुनाव में बार–बार लड़ना नहीं चाहता है। चुनाव महंगा भी हो गया है और चुनाव में अनिश्चितताएं भी बहुत है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक बिस्मार्क के अनुसार "राजनीति संभव करने की कला है"। वैसे भी राजनेता केवल राष्ट्रहित और सेवा के बारे में ही नहीं सोचते कई बार राष्ट्रहित से पहले उनका व्यक्तिगत अस्तित्व आगे आ जाता है।

मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन फिलहाल सरकार बनने से दूरी बना लिया है क्योंकि राजनीतिक माहौल उसके अनुकूल नहीं था लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं लगाया जाना चाहिए की इंडिया गठबंधन आगे राजनीति नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन तब तक इंतजार कर सकता है जब तक उसके पक्ष में परिस्थितियां निर्मित नहीं होती लेकिन जिस दिन उसे लगेगा कि उसका पलड़ा भारी हो रहा है वह फिर खुलकर राजनीति करने लगेगा। इंडिया गठबंधन आगे भी टीड़ीपी और जदयू को लुभाने का भी काम जारी रखेगा। दोनों पार्टियों के भीतर असंतोष के बीज बोने की कोशिश करेगा। वैसे भी भाजपा का टीडीपी और जदयू के साथ पहले से ही 'कभी प्यार, कभी नफरत' वाला रिश्ता रहा है। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से दोनों दलों के नेताओं का आना–जाना भी लग रहा है। मौके की तलाश इस तरफ भी रहेगी।

लेकिन नई सरकार के बनने के बाद यह माना जा रहा है कि इसका सकारात्मक परिणाम यह होगा कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब बहुसंख्यकवादी लाइन पर उस तरह नहीं चल पाएगी जैसे पहले के दो कार्यकालों में चलकर दिखाया था। भाजपा को अपने बुनियादी आधारों से भी समझौता करना पड़ सकता है जिसे आगे कर पार्टी ने चुनाव लड़ा था। मसलन समान नागरिक संहिता, मुसलमान के लिए कोटा जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए निराशाजनक हो सकते हैं।

कुल मिलाकर एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना की एक सक्षम सरकार। प्रचंड बहुमत अहंकार को जन्म दे सकता है। वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा के बहुसंख्यकवाद को चोट पहुंची है। आत्मविश्वास से लबालब पार्टी लोगों के आर्थिक दुखों और स्थानीय मुद्दों को समझने में विफल रही है। लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और विश्वसनीय व्यवहार विकल्प पेश करना चाहिए।यह देखना होगा कि विपक्षी भारतीय गुट आगे भी क्या एक साथ रहेगा और सरकार के लिए अनावश्यक बाधाएं पैदा करने के बजाय देश की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार के साथ खड़ा होगा और रचनात्मक आलोचना के साथ संसदीय भूमिका को चतुराई से निभाएगा या नहीं? जाहिर है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ❑❑

नई सरकार, पर अपेक्षा वही

लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई है और अब भाजपा के नेतृत्व में राजग की नई सरकार बन गयी है। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से कठिनाई यह होती है कि सरकार कमजोर रहती है। भारत में फिर एक बार राजकीय अस्थिरता का दौर चल पड़ा है। देखना पड़ेगा कि यह अस्थिरता मध्यवर्ती चुनाव की ओर ले जाती है या फिर पाँच साल सरकार चलने देती है। कुछ भी हो, यह तय है कि अब सरकार धाकड़ निर्णय नहीं ले पाएगी और भारत की विकास गति धीमी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी वह भी शायद अब नहीं रहेगी। और इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जहां तक सरकार से अपेक्षा की बात है, अपेक्षा तो बदली नहीं है। नई कमजोर और अस्थिर सरकार शायद इसे पूरा करने में भी सक्षम नहीं होगी। फिर भी कुछ सामान्य अपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना ही होगा। इसमें सरकार कुछ करती है तो उपयुक्त होगा।

किसान समृद्धि की ओर कदम जरूरी

भारतीय किसान बाजार और पर्यावरण में हो रहे बदलाव से तंग है। कृषि बाजार संबंधी तीन कानून वापस लेने से सभी कुछ अस्पष्ट सा हुआ है। यह सच है कि बाजार के चढ़ाव–उतार से होने वाले नुकसान से बचने के लिए दिया जा रहा फसल कीमत संरक्षण और संबंधित समर्थन मूल्यों पर सरकार की फसल खरीदी से किसान खुश नहीं है। वैसे भी इस व्यवस्था का लाभ भारत के कुछ ही क्षेत्र के किसानों और फसलों को मिलता है। भारत के सभी क्षेत्रों के किसान और सभी क्षेत्रीय फसलें जब तक इस व्यवस्था का भाग नहीं होती तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। उसी तरह फसल बीमा भी किसान के आए दिन होने वाले नुकसान को कम नहीं कर पा रही है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना होगा। किसान सम्मान निधि भी किसान को खुश नहीं कर पाया है क्योंकि उसका नाता किसान के नुकसान

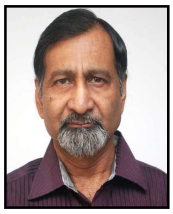

नई सरकार के अस्थिर और अल्पमत में होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और देश में बाहरी ताकतों का अंदरूनी विद्रोही से मिलकर आतंकवाद फैलने का डर सबसे ज्यादा है। शायद यही नई सरकार को चुनौती है।

–अनिल जवलेकर

से किसी भी तरह से नहीं है। अच्छा होगा इसका नाता किसान की आय से हो। किसान की आय उसकी जमीन, फसल उत्पादन और उसकी उत्पादकता तथा उसकी बिक्री से आती है। फसल के बाजार मूल्य उसे प्रभावित करते है और किसान आय के प्रति सशंकित रहता है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना अगर राष्ट्रीय स्तर पर अमल में लाई जाये तो शायद किसान को राहत मिल सकती है। यह जरूरी है कि सरकार की मंशा और कदम किसान की आय को सुनिश्चित करना होना चाहिए। अगर किसी कारणवश फसल का नुकसान होता है तो किसान को बिना विलंब नुकसान भरपाई मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को जिम्मेवारी के साथ करनी चाहिए। सम्मान निधि भी किसी तरह से इस आय को सुनिश्चिति करने में उपयोगी होती है, तो अच्छा होगा।

रोजगार उपलब्ध करने होंगे

सुशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था रोजगार के लिए जरूरी कौशल देने में नाकाम रही है और इसमें आमूल–चुल बदल की आवश्यकता है। कौशल निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयास इस शिक्षण व्यवस्था का एक हिस्सा होना जरूरी है। नहीं तो यह व्यवस्था पदवी तो देती रहेगी, लेकिन युवाओं को रोजगार दिलाने में उपयोगी नहीं रहेगी। उत्पादन उद्योग की भूमिका रोजगार निर्माण में कम नहीं आंकी जा सकती। भारत को अपना उत्पादन क्षेत्र बढ़ाना ही होगा। साथ ही बदलते तंत्र ज्ञान युग में स्वचालित यांत्रिकी आने से उत्पादन उद्योग में भी बदलाव हो रहा है और रोजगार कम उपलब्ध हो रहे है। इसको भी ध्यान में रखकर ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना होगा, और स्वरोजगार बढ़ाने होंगे तभी बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल हो सकता है।

भारत में राजकीय नैतिक आचरण बहुत ही निचले स्तर पर जा रहा है। इसलिए इसमें कानूनी तौर पर कुछ करने की जरूरत है। जेल में बंद होने की बावजूद जेल से सरकार चलाने की भाषा लोकतंत्र के लिए हानिकारक मानी जानी चाहिए और इसलिए कानूनी बदलाव होने चाहिए। उसी तरह न्यायालय ने नेताओं को राजकीय कारणों से जेल से रिहा करने की नई परंपरा शुरू की है। उसे भी लगाम लगना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया में न्याय व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत आन पड़ी है।

पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी

पर्यावरण बदल रहा है और उसकी जिम्मेवारी भी मानव जाति पर है। समस्या समझ आने पर भी कुछ करने की बात सिर्फ मौखिक सहानुभूति तक सीमित है। इसे जन आंदोलन का रूप देने से ही कुछ हो सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना तो इसमें है ही लेकिन ई–वेस्ट की समस्या भी बढ़ रही है। अपने आस–पास का पर्यावरण शुद्ध रखने के प्रयास हर स्तर पर होना जरूरी है। सरकार को यह आंदोलन जन आंदोलन बनें, ऐसे प्रयास करने होंगे।

राजनीतिक व्यवस्था नैतिक हो, यह जरूरी

भारत में राजकीय नैतिक आचरण बहुत ही निचले स्तर पर जा रहा है। इसलिए इसमें कानूनी तौर पर कुछ करने की जरूरत है। जेल में बंद होने की बावजूद जेल से सरकार चलाने की भाषा लोकतंत्र के लिए हानिकारक मानी जानी चाहिए और इसलिए कानूनी बदलाव होने चाहिए। उसी तरह न्यायालय ने नेताओं को राजकीय कारणों से जेल से रिहा करने की नई परंपरा शुरू की है। उसे भी लगाम लगना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया में न्याय व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत आन पड़ी है।

चुनाव सुधार को प्राथमिकता देनी होगी

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ रहा है। इसलिए चुनाव सुधार जरूरी है। चुनाव में राजकीय पक्षों का महत्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनकी जिम्मेवारी तय नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र, उसमें किए जा रहे वादे, गुनहगार उम्मीदवार, मुफ्त में दी जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के वादे भारतीय लोकतंत्र को खोखला और अर्थव्यवस्था पर बोझ होती जा रही है। इसका हल समय रहते ही ढूंढना जरूरी है। यह जरूरी है कि एक भी गुनहगार चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले सके, ऐसी व्यवस्था हो। गुनहगार की व्याख्या ही बदलनी होगी और हर तरीके से चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ करनी होगी।

नई सरकार के अस्थिर और अल्पमत में होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और देश में बाहरी ताकतों का अंदरूनी विद्रोही से मिलकर आतंकवाद फैलने का डर सबसे ज्यादा है। शायद यही नई सरकार को चुनौती है। इससे निपटकर समाज और देश हित के लिए कानूनी बदलाव लाकर उन्नति की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाना, एक कठिन सा काम है। आशा है भाजपा नेतृत्व की नई सरकार देशहित में काम करने से नई चूकेगी। ❑❑

क्या-क्या बदलने वाला है इस चुनाव परिणाम के बाद?

किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि अब देश में बहुत कुछ बदल जाना है। 10 साल के बाद फिर से गठबंधन की सरकार जब चलेगी, तो फैसले उस तरह से नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लिया करते थे।

त्वरित फैसलों से होने वाले बदलाव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा था कि भारत में कोई पॉलिसी पैरालिसिस था। उन्हीं फैसलों की बदौलत एनडीए 10 साल लगातार यह दावा करता रहा कि उसने देश का कायापलट कर दिया है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अब तीसरे पायदान पर पहुँचने वाली है। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब केवल चीन व अमेरिका से ही कुछ दूरी पर रहेगा। कहा यह भी जाने लगा था कि जिस तरह से चीन की हालिया आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं और उसका पतन जिस तेजी से हो रहा है, उसमें भारत का ऊपर की ओर बढ़ना और निश्चित हो गया है और वह 2030 तक चीन के काफी करीब भी पहुँच सकता है।

यह सच है कि भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत और संरचनात्मक रूप से ठोस नजर आ रही है। पिछले कुछ सालों में कानून प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। कोई बड़ा भ्रष्टाचार सतह पर नहीं आया और इतनी बड़ी आबादी को राशन, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करते नहीं देखा गया। हालांकि चुनाव परिणाम यह नहीं बताते कि जनता पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट थी। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में मिले अवसर का लोगों ने देश की परंपरा के अनुसार अहिंसक बदलावों के लिए इस्तेमाल किया और अब एक अंकुश के साथ सरकार बनाने या चलाने का जनादेश दिया। स्पष्ट है कि इस चुनाव के बाद सरकार के काम काज के तरीके में बदलाव दिखेगा ही। हालांकि चुनावी विफलताओं के लिए केवल नेतृत्व को दोषी नहीं ठहरा सकते।

किसी भी देश को एक ऐसे नेता की जरूरत होती है, जो समय और ऊर्जा देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में लगा सके। उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए और वह अपने परिवार के लिए धन संचय करता हुआ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी लगभग खरे उतरते हैं।

– विक्रम उपाध्याय

वर्तमान वैश्विक परिस्थियों में किसी कमजोर सरकार का होना आंतरिक और बाहरी दुनिया में भारत की संभावनाओं को सीमित ही करेगा। आर्थिक नीतियों में कोई भी विचलन आशाजनक परिस्थितियों को निराशा में बदल सकता है, खास कर इस नजरिए से कि कई देश गहरी मंदी में हैं। आज भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के तेज़ विकास के जरिए विकासशील देशों में अपने नंबर ऊपर कर के विकसित देश होने की ओर अपनी बढ़त बनाए रखने की जरूरत है। यह तभी संभव है कि भारत के निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। पर पहले से ही कुछ घरानों के लिए काम करने के विपक्ष के आरोप के बाद सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा या फिर उसमें बदलाव होगा। चुनाव में राहुल गांधी द्वारा अदानी–अंबानी के मुद्दे उठाए गए और इन मुद्दों पर तालियाँ मिलीं भी। क्या सरकार फिर से उन्हीं मुद्दों के आगे निर्भीक रह सकेगी?

भारत की सेना दुनिया में इस समय चौथी सबसे मजबूत सेना है। इसको और आगे ले जाने के लिए वित्तीय संसाधन के साथ सेना के प्रति लोगों में विश्वास और युवाओं में इससे जुडने की ललक भी जरूरी है, क्योंकि सेना भी जनसांख्यिकी प्रभावों से अछूती नहीं रह सकती। 2025 तक भारत अपनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने का ब्लू प्रिन्ट तैयार कर चुका है। लेकिन सेना में नियुक्ति को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल इन दिनों तैयार करने की कोशिश की गई।

अग्निवीरों के बारे में जिस तरह के दावे किये गए और इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से खुलेआम कहते रहे कि सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर की योजना निरस्त कर देंगे, उससे युवाओं में असमंजस का भाव घर कर गया है। चूंकि मोदी की निवर्तमान सरकार ने अग्निवीरों में से ही नियमित सेना के

भारत की सेना दुनिया में इस समय चौथी सबसे मजबूत सेना है। इसको और आगे ले जाने के लिए वित्तीय संसाधन के साथ सेना के प्रति लोगों में विश्वास और युवाओं में इससे जुडने की ललक भी जरूरी है, क्योंकि सेना भी जनसांख्यिकी प्रभावों से अछूती नहीं रह सकती। 2025 तक भारत अपनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने का ब्लू प्रिन्ट तैयार कर चुका है। लेकिन सेना में नियुक्ति को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल इन दिनों तैयार करने की कोशिश की गई।

जवानों की नियुक्ति का प्रावधान किया है, तो बहुत हद तक संभव है कि सैन्य नियुक्ति नियमों में भी कुछ बदलाव हो। अग्निवीरों की अभी यह शुरुआती खेप है। भारत को अपने सैन्य आधार को मजबूत करने के लिए इस योजना के प्रति युवाओं में विश्वास बहाल करना ही होगा। किसी भी संदेह की गुंजाइश भारत के लिए कुशल सैन्य शक्ति बनाने में देरी या कमजोरी का कारण बन सकती है। केवल विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकास से ही सेना मजबूत नहीं हो सकती।

किसी भी देश को एक ऐसे नेता की जरूरत होती है, जो समय और ऊर्जा देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में लगा सके। उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए और वह अपने परिवार के लिए धन संचय करता हुआ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी लगभग खरे उतरते हैं। लेकिन उन्हीं पर विपक्ष ने यह तोहमत लगाया है कि उन्होने गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया और अपनी छवि को ज्यादा महत्व दिया।

कहा गया कि मोदी ने खुद को ऐसा प्रोजेक्ट किया कि उनके जैसे एक मजबूत नेतृत्व के रूप में खड़े होने के बाद देश को अब और मजबूत नेताओं की जरूरत ही नहीं है। उनका आत्म केंद्रित अवतार ही उनकी कमजोरी का कारण बन गया। हालांकि उन पर निहित स्वार्थों के लिए काम करने का कोई आरोप नहीं लगा। पर समूहों के बीच नफरत और आंतरिक संघर्षों को कम करने के प्रति उनकी भूमिका पर लोगों ने सवाल जरूर उठाया। मशहूर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर की यह उक्ति है कि– "प्रभावी नेतृत्व का मतलब भाषण देना या पसंद किया जाना नहीं है; बल्कि परिणामों से होता है।"

चुनाव में कॉंग्रेस को जो भी सफलता मिली, उसे उस पार्टी के नेता जनता से मिली सहानुभूति और करुणा का प्रतिफल बता रहे हैं। अलग–अलग संस्कृति, धर्म और भाषाओं के बीच सेतु बनने के प्रयास को इसका श्रेय देते हैं। वे देश को एक सूत्र में पिरोकर सबको आगे बढ़ाने की भी बात करते हैं। कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की पहल का दावा करते हैं। क्या इससे भारत की राजनीति में कुछ बदलाव होगा। ये सारी बातें बनावटी भी हो सकती हैं, लेकिन इस बार इसके साथ सफलता, चुंबक में लोहे जैसी चिपक गई है, तो संभावना है कि कुछ दिन के लिए पोलिटिकल नैरेटिव भी बदल जाए। सबका साथ, सबका विकास का कोई नया शोधन शब्द सामने आ जाए और अब लोगों में दोष खोजने के बजाय, व्यवस्था में सुधार परिलक्षित हो।

https://hindi.oneindia.com/opinion/what-is-going-to-change-after-this-election-result-2024-1022799.html

"पड़ोसी पहले और सागर दृष्टिकोण" वाली नीति को तवज्जो

नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस बार भाजपा की सरकार राजग गठबंधन पर निर्भर रहेगी क्योंकि भाजपा स्पष्ट बहुमत के 272 के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई है। हालांकि शपथ के साथ ही मोदी ने न केवल समझौतावादी जनादेश स्वीकार किया बल्कि पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों को शपथ के अवसर पर आमंत्रित कर उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखने का उदार संदेश भी दे दिया है।

गणतंत्र के इस समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगननाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हुए। भारत की ओर से यह पहल 'पड़ोसी पहले और सागर दृष्टिकोण' की नीतियों को कारगर बनाने की दृष्टि से की गई है। साफ है, पड़ोसी और समुद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेंगे। 2014 में मोदी ने सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों और 2019 में बिम्सटेक यानी बंगाल की खाड़ी की पहल से जुड़े देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इन देशों में भारत क्षेत्रफल, आबादी और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दस साल पहले मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 11वां स्थान था, जो मोदी के 10 साला कार्यकाल में 3.70 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के आकार के साथ विश्व में पांचवें स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के जानकार उम्मीद जता रहे हैं कि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मन की आर्थिकी से

पाकिस्तान को छोड़ अन्य पड़ोसियों को शपथ समारोह में आमंत्रित किया जाना साफ संदेश है कि नरेन्द्र मोदी उदार तो हैं, लेकिन आतंकवाद की सरपरस्ती करने वाले देश के प्रति कठोर भी हैं।

–शिवनंदन लाल

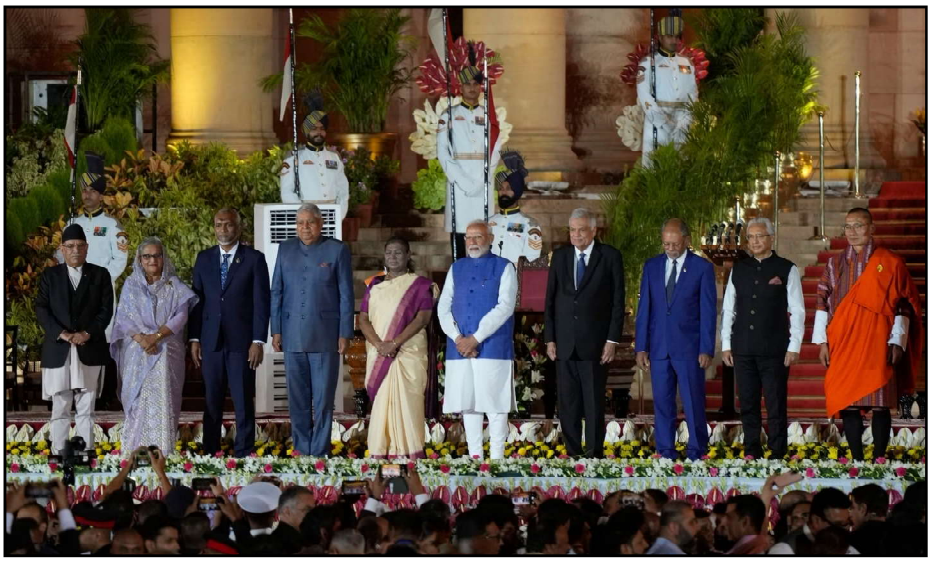

आगे निकल कर वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर होगी और 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था।

भारत ने उदारता दिखाते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु को आमंत्रित किया जबकि 2023 में जबसे मोइज्जु मालदीव के राष्ट्र प्रमुख बने हैं तभी से मालदीव और भारत के संबंधों में तनाव बना हुआ है। अपने चुनाव अभियान के दौरान मोइज्जु ने भारत के 88 सैनिकों को देश से निकालने का आह्वान किया था। किंतु अब मोइज्जू ने कहा है कि उनके लिए इस ऐतिहासिक अवसर में भागीदारी सम्मान की बात है। उम्मीद है कि अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। दक्षेस मसलन हमारे वे पड़ोसी देश जो हमारी जमीनी अथवा समुद्री सीमा से जुड़े हैं। इन देशों की संख्या 8 है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। हालांकि चीन भी हमारी सीमा से जुड़ा है, लेकिन दक्षेस का सदस्य नहीं है। इस समूह में यदि मॉरिशस, ईरान, म्यांमार और मध्य एशिया के पांच गणराज्य भी शामिल हो जाएं तो इसकी ताकत वैश्विक मुद्दों में हस्तक्षेप के लायक बन सकती है। दक्षेस देश दुनिया के तीन फीसद भूगोल में फैले हैं। दुनिया की मौजूदा आबादी की 21 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं देशों में

दक्षेस मसलन हमारे वे पड़ोसी देश जो हमारी जमीनी अथवा समुद्री सीमा से जुड़े हैं। इन देशों की संख्या 8 है। ये देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। हालांकि चीन भी हमारी सीमा से जुड़ा है, लेकिन दक्षेस का सदस्य नहीं है।

है। इन देशों में कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 70 फीसद से ज्यादा है। 80 फीसद आर्थिकी पर भी भारत काबिज है। हालांकि वैश्विक कारोबार की तुलना में इन देशों का परस्पर कुल व्यापार 5 फीसद ही है। इस लिहाज से ये देश न तो व्यापार के क्षेत्र में सफल रहे और न ही शांति बरकरार रखने में कामयाब हुए। इस नाते इस संगठन का ज्यादा महत्त्व नहीं रह गया है। पाक निर्यातित आतंक कालांतर में युद्ध का कारण बनता है तो दक्षेस का भंग होना तय है। मोदी न केवल दक्षेस, बल्कि आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार के पक्षधर हैं लेकिन पाक बाधाएं पैदा करने से बाज नहीं आता।

मोदी आतंकवाद के प्रखर विरोधी रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ उनकी मुखरता के चलते आज भारत समेत दुनिया में आतंकवाद कमजोर हुआ है। गौरतलब है कि दक्षेस के गठन में पाकिस्तान की अहम भूमिका थी। पाक के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इस परिकल्पना को अंजाम तक पहुंचाया था। 1981 में भारत समेत अन्य दक्षेस देशों के विदेश सचिवों की पहली बैठक बांग्लादेश में हुई थी। बाद में 1983 में विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई और इसी बैठक में 'दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन' वजूद में आया किंतु अब पाकिस्तान चीन के कर्ज में फंसकर उसके इशारों पर नाचने को मजबूर है। भारत–पाक के संबंध आजादी के बाद से ही नरम–गरम बने रहे हैं। जम्मू–कश्मीर के 78,000 वर्ग किमी. भूभाग पर पाकिस्तान का अतिक्रमण है। नियंत्रण रेखा के उल्लंघन और सीमा पार से गोलीबारी और आतंकी गतिविधियां जारी हैं। बार–बार इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांगों को पाकिस्तान अनदेखा करता रहा ने दिलचस्पी नहीं ले रहा। अतएव पाकिस्तान को छोड़ अन्य पड़ोसियों को शपथ समारोह में आमंत्रित किया जाना साफ संदेश है कि नरेन्द्र मोदी उदार तो हैं, लेकिन आतंकवाद की सरपरस्ती करने वाले देश के प्रति कठोर भी हैं। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

सतत विकास के लिए रचनात्मक और नवाचार

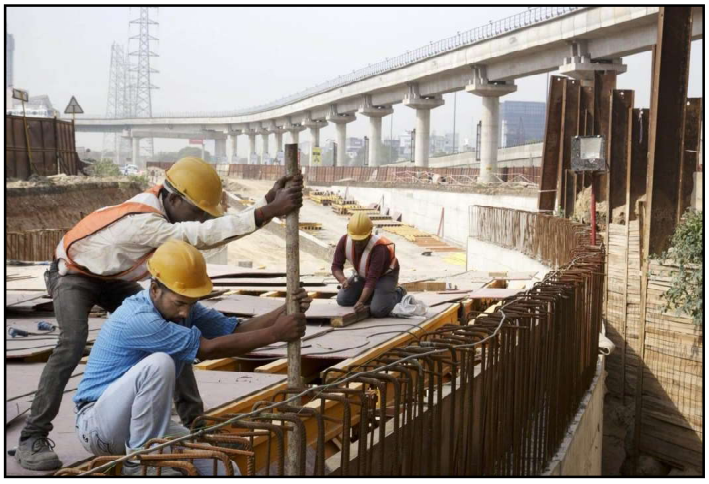

सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास को बढ़ावा देने में रचनात्मक और नवाचार के महत्व को मान्यता देते हुए 17 लक्ष्यों को शामिल करते हुए "हमारे विश्व को बदलनाः सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" जारी किया था। एजेंडा में गरीबी दूर करना असमानता को खत्म करना, ग्रहों की रक्षा करने के साथ–साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए खुशहाली तथा समृद्धि सुनिश्चित करने की योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। दरअसल विकसित भारत@2047 के लिए यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पोस्ट भी है।

मालूम हो कि सृजनात्मक नए विचारों को सृजित करने के लिए कल्पना, सोच और कौशल का उपयोग है, जबकि नवाचार मौजूदा विचारों को बेहतर बनाने या नए उत्पाद विकसित करने के लिए सृजनात्मकता, ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल की उपलब्धता और स्वच्छता तथा गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता के आधार पर रेखांकित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई मौके पर शून्य बेरोजगारी के लिए उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की वकालत की है। इन लक्ष्यों को नवाचार और नए विचारों तथा रचनात्मकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

विकासशील भारत@2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मक ही सही दिशा है जहां हमारे युवा जो कि विश्व स्तर पर संख्या में सबसे अधिक हैं वे धरती माता की रक्षा तथा देश के विकास और समृद्धि के लिए इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 21 अप्रैल के दिन को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए 27 अप्रैल 2017 को एक संकल्प पत्र पारित किया। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17 में सत्र में 79वीं पूर्ण बैठक के दौरान इसका निर्णय किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में हर साल 26 अप्रैल को विश्व आईपी दिवस भी मनाया जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बैनर तले आयोजित किया जाता है। आईपी और इनोवेशन दो अलग–अलग अवधारणाएं हैं हालांकि एक दूसरे के पूरक हैं।आईपी या बौद्धिक संपदा आईपीआर या बौद्धिक संपदा अधिकारों की ओर ले जाती है जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा विनियमित बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपी राइट्स आदि के लिए अलग–अलग आईपीआर कानून के तहत संरक्षित है। नवाचार का अर्थ नए विचारों को उत्पादों में उपयोग करना और रचनात्मक या बौद्धिक संपदा का व्यवसाय कारण करना है।

नवाचार, विपणन, वित उत्पादन यहां तक की शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन के किसी भी सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है। इस प्रकार नव प्रवर्तन एक बहुत व्यापक शब्द है और इसके पीछे किसी आईपीआर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आर्थिक विकास के लिए समाज को स्कूलों में युवा दिमाग के विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। साथ ही साथ नए विचारों को धर्म या सामाजिक पूंजी या मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए इसका पोषण होना चाहिए। आज का समय ज्ञान का समय है। ज्ञान के इस युग में भारत जैसे देश के लिए जहां हमारे पास दुनिया का सबसे समृद्ध मानव संसाधन है। उचित शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का जबरदस्त अवसर है। भारत सरकार ने नीति आयोग के तहत अटल इन्नोवेशन मिशन 2016 स्थापित

कर इस दिशा में एक प्रमुख पहल की है। अटल इन्नोवेशन मिशन के जरिए सभी जिलों के स्कूलों में अटल तिकरिंग लैब अटल इनक्यूबेटर और अटल कम्युनिटी इन्नोवेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं जो की नए स्टार्टअप को सहायता प्रदान करते हैं।

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग धरती माता के लिए एक बड़ी समस्या है। जी–20 की बैठक के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य की बात की और इसे दिल्ली घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया गया। ग्रीन हाउस गैस या ब्लैक कार्बन सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश को अवशोषित करता है। बादल निर्माण और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है, जिससे हिंसक तूफान, बारिश और बाढ़ आती है। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तटीय क्षेत्र के अनेक बाशिदें पहले से ही जलवायु शरणार्थी बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण कैंसर सहित न्यूरोलॉजिकल सांस और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियों का कारण बन रहा है। विश्व बैंक में अनुमान लगाया है कि वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की लागत प्रतिवर्ष 8.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 6.1 प्रतिशत के बराबर है। इसलिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। आज नवाचार के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आया है और डब्ल्यूईपीओ पेटेंट विश्लेषण के अनुसार 15.02 मिलियन से अधिक सक्रिय पेटेंट में से 4.5 7 मिलियन से अधिक पहले से ही एसजी से जुड़े हुए हैं और यह भी बताया गया है की 31.4 प्रतिशत सक्रिय पेटेंट टिकाऊ और सतत विकास के लक्ष्य को संबोधित कर रहे हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इन्नोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां है। वर्ष 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। अपनी विशाल ज्ञान पूंजी जीवन स्टार्टअप पर स्थित की तंत्र अंतरिक्ष विभाग जैव प्रौद्योगिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारत में ऊंची छलांग अर्जित की है। इस बीच नीति आयोग भी इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा के लिए नीति आधारित नवाचार लाने के लिए अनुकूलन सुनिश्चित करने हेतु अथक प्रयास कर रहा है।

भारत की ओर से यह प्रगति तब है जब भारत अनुसंधान एवं विकास के मोर्चे पर बहुत कम खर्च करता है। अनुसंधान और विकास पर भारत का खर्च दुनिया में सबसे कम है। अनुसंधान और विकास पर भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत से भी कम खर्च करता है जबकि चीन 2.43 प्रतिशत, जापान 3.3 प्रतिशत, जर्मनी 3.4 प्रतिशत और अमेरिका 3.46 प्रतिशत खर्च करता है। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसंधान और विकास पर निजी क्षेत्र का खर्च व्यावहारिक रूप से शून्य है और जो भी थोड़ा बहुत खर्च होता भी है तो वह फार्मास्यूटिकल और आईटी क्षेत्र के लिए होता है। भारत में अनुसंधान और विकास पर खर्च का एक बड़ा हिस्सा लगभग दो तिहाई सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

हमें रचनात्मक और नवीनता के बीच अंतर को भी समझना होगा। रचनात्मक नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए बुद्धि का कार्य है लेकिन नवाचार इस मूर्त उत्पादों में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति प्रौद्योगिकी के किसी विशेष क्षेत्र यहां तक कि व्यवसाय में सुधार के लिए अपने विचारों में बहुत रचनात्मक हो सकता है और एक बहुत अच्छा दस्तावेज या शोध पत्र तैयार कर सकता है, लेकिन एक प्रवर्तक एक उद्यमी होता है जो अपने विचार को उत्पादन में परिवर्तित करता है। वह एक नया उत्पाद तैयार कर सकता है चाहे वह नई मशीन हो कि वहां हो या मोबाइल का कोई नया ऐप हो जिसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार आविष्कार और नव प्रवर्तन में भी अंतर है। अविष्कार आमतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होता है जो सैद्धांतिक रूप से होता है या प्रयोगशाला में भी आजमाया जाता है हालांकि एक नवाचार कई प्रयासों के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप की तलाश करेगा और अंततः एक दवा या मोटरकार, एक इंजन या एक हवाई जहाज के रूप में एक नया उत्पाद सामने ला सकता है। इसलिए विचारों को विकसित करने के लिए उचित समन्वय और आविष्कार के लिए अनुसंधान सुविधा प्रदान करने इससे संबंधित स्टार्टअप के लिए उचित उद्यम पूंजी निधि के लिए सहयोगी दृष्टिकोण के साथ–साथ एक व्यवहारिक परिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जिससे एक उद्यमी वास्तव में कुछ जोखिम उठाकर भी नए उत्पाद बना सके।

हाल के दिनों में निजी उद्योगों द्वारा स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ अनूठी पहल की जा रही है। ऐसा ही एक स्टार्ट अप इंडिया एक्सलेरेटर है जिसने भारतीय सेवा के अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत के नेतृत्व मेंसमर्पित टीम की मदद से मानव रहित हवाई प्रणालियों काउंटर ड्रोन और ग्राउंड रोबोटों को रणनीतिक समर्थन प्रदान करने के लिए एक नया वर्टिकल मानव रहित रोबोटिक्स लॉन्च किया है। इसी तरह श्रीधर बंबू की जोहो कारप ने भी वैश्विक स्तर पर चिकित्सा निगरानी और लॉजिस्टिक के लिए ड्रोन समाधान प्रदान करने वाले ड्रोन स्टार्टअप याली एयरोस्पेस में निवेश किया है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न और एक लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है और यह संख्या आगे और भी तेजी के साथ बढ़ाने की संभावना है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विकासशील भारत@2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नवाचार और रचनात्मक ही सही दिशा है जहां हमारे युवा जो कि विश्व स्तर पर संख्या में सबसे अधिक हैं वे धरती माता की रक्षा तथा देश के विकास और समृद्धि के लिए इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ❑❑

लेखक, निदेशक–स्वदेशी शोध संस्थान एवं राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच।

अर्थव्यवस्था में आगे भी मजबूती के संकेत

कोरोना महामारी के कारण अस्त–व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने बैंकिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए जिन अनेक योजनाओं और पहलों को मूर्त रूप दिया, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति में है। राजग की सरकार के केंद्र में आने के बाद यह उम्मीद बढ़ी है कि सरकार अपनी पुरानी नीतियों पर कायम रहेगी, जिससे अर्थव्यवस्था और बैंकों को और भी मजबूती प्राप्त होगी। सरकार के सम्मिलित प्रयासों का ही नतीजा रहा कि वर्ष 2023–24 के दौरान सभी बैंकों के शुद्ध फंसे कर्ज (एनपीए) घटकर 1.70 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने के बाद ढेर सारे आर्थिक विश्लेषको ने राजनीतिक जोड़तोड़ और अस्थिरता को आगे कर विकास की गति धीमा पड़ने की आशंका व्यक्त की है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बैंकों का मुनाफा बढ़ रहा है। विकास कार्य भी प्रगति पर है। निर्मला सीतारमण के हाथों में दोबारा वित्त मंत्रालय का कामकाज मिलने के बाद इस संभावना को बल मिला है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और उठाए जाने वाले कदम आगामी समय में भी भारतीय बैंकों के अनुकूल रहेंगे।

इधर के दिनों में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन एशिया में अपने समकक्ष बैंकों की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। देश के तीन बड़े बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 2023 में दुनिया के सिर्फ 50 बैंकों की सूची में अपनी जगह बनाई है, जबकि वर्ष 2022 में देश के सिर्फ दो बैंकों ने दुनिया के सिर्फ 50 बैंकों में अपनी जगह बनाई थी। एस. एंड पी. ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय स्थिति में सुधार, मजबूत आर्थिक स्थिति, कर्ज में तेज वृद्धि, एनपीए में कमी और मुनाफे में वृद्धि से भारतीय बैंक

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और उठाए जाने वाले कदमों के कारण आने वाले समय में भी भारतीय बैंक आगे बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था अनुकूल रहेगी।

–अनिल तिवारी

मजबूत हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बैंकों की संपत्ति 50.5 प्रतिशत बढ़कर 1.5 1 लाख करोड डालर हो गई है। जुलाई 2022 में एचडीएफसी बैंक की संपत्ति 51.3 प्रतिशत बढ़कर 466.35 अरब डालर हो गई इससे बैंक शीर्ष 50 की सूची में तेरह पायदान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर पहुंच गया है।

आर्थिकी पर नजर रखने वाली एजेंसी के मुताबिक हाल के महीना में भारतीय बैंकों द्वारा दिए जा रहे कर्ज में तेज वृद्धि हुई है। 29 दिसंबर 2023 तक यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी, जो 1 साल पहले 14.9 प्रतिशत ही थी। वित्त वर्ष 2023–24 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा और केनरा बैंक में 10000 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने तो इस वर्ष में 61077 करोड रुपए का मुनाफा हासिल किया है जो सरकारी बैंकों की कुल कमाई के 40 प्रतिशत से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक में 50232 करोड रुपए का मुनाफा कमाया था। बारह सरकारी बैंकों में से सिर्फ पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। 31 मार्च 2024 को सरकारी बैंकों का संचयी लाभ 1.4 लाख करोड रुपए के स्तर को पार कर गया जो पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2022–23 में सरकारी बैंकों ने 104649 करोड रुपए का शुद्ध लाभ वर्जित किया था। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक का शुद्ध मुनाफा 8245 करोड रुपए रहा जो पिछले साल के मुकाबले 228 प्रतिशत अधिक है, जबकि यूनियन बैंक आफ इंडिया ने 13649 करोड रुपए का मुनाफा कमाया था जो पिछले साल की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक है। अन्य सरकारी बैंकों जैसे सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 61 प्रतिशत, बैंक आफ इंडिया ने

वित्त वर्ष 2018 में सरकारी बैंकों को 50390 करोड रुपए का घाटा होने के बाद यह 2024 में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने के सफर की ऐसी कहानी है जो आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के और अधिक मजबूत होने का संकेत दे रही है।

57 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र में 56 प्रतिशत और इंडियन बैंक ने 53 प्रतिशत अधिक मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2018 में सरकारी बैंकों को 50390 करोड रुपए का घाटा होने के बाद यह 2024 में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने के सफर की ऐसी कहानी है जो आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के और अधिक मजबूत होने का संकेत दे रही है।

ज्ञात हो कि राजग सरकार वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान सरकारी बैंकों के साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही और 310997 करोड रुपए का पुनर्पूंजीकरण भी सरकारी बैंकों का किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मामले में इस दौरान सुर में सुर मिलाते हुए आवश्यक कदम उठाए। इन सम्मिलित प्रयासों से वित्त वर्ष 2023 24 में सभी बैंकों का शुद्ध फंसा कर्ज घटकर 1.70 प्रतिशत के स्टार के नीचे आ गया।

अब राजग की केंद्र में फिर से तीसरी बार सरकार बन चुकी है, और वित्त मंत्रालय का कामकाज एक बार फिर निर्मला सीतारमण के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद से ही इस तरह की कयास लगाई जा रही है की सरकार की स्थिरता को लेकर संकट बने रहेंगे। विकास के काम भी प्रभावित हो सकते हैं वहीं आर्थिक गतिविधियों में भी कई तरह की रुकावटें खड़ी हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में निरंतर इजाफा हो रहा है। एनपीए की मात्रा लगातार घट रही है। कई आवश्यक और महत्वपूर्ण मानकों पर भारतीय बैंक अपना उम्दा प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इन तेज गतिविधियों को देखते हुए अब अधिकांश आर्थिक जानकार भी कहने लगे हैं कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और उठाए जाने वाले कदमों के कारण आने वाले समय में भी भारतीय बैंक आगे बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था अनुकूल रहेगी। ❑❑

मोदी सरकार में विज्ञान की प्रगति

पिछले दिनों प्रकाशित हुए लेखों के माध्यम से ऐसा स्थापित करने का प्रयास किया गया कि मोदी सरकार के दौर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में विशेष प्रगति नहीं हुई, और वर्ष 2024 के बाद मोदी सरकार बनने की स्थिति में भारत में विज्ञान की स्थिति और कमजोर होगी। इन विद्वानों की माने तो विज्ञान के अलावा पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीकरण, डिजिटाइजेशन, वित्तीय और कानून सुधार, युवा और महिला विकास, खेल सुधार, तकनीकी शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और रक्षा उत्पादन क्षेत्र में हुए बड़े नीतिगत सुधारों में भी इन्हें मोदी सरकार का कोई योगदान नज़र नहीं आता।

हालांकि इन सबके उलट अगर हम तथ्यात्मक अवलोकन करें तो पाएंगे कि शिक्षा और तकनीक को केंद्र में रखा। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान की दिशा में कई बड़े बदलाव हुए हैं। यह मोदी सरकार के पिछले दस वर्षों में था कि यूजीसी द्वारा विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जेआरएफ और एसआरफ फेलोशिप की राशि को 2014 और 2019 में दो बार बढ़ाया गया था।

एस.एण्ड.टी. कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ वित्तीय प्रतिबद्धता आवश्यक है क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं लंबी अवधि की होती हैं। मोदी सरकार की अवधि में सकल जीडीपी का अनुसंधान एवं विकास व्यय 2010–11 में रू. 60,000 करोड़ से दोगुना होकर पिछले वर्ष रू. 1.2 लाख करोड़ हो गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का कुल व्यय 2013–14 में लगभग रू. 3,200 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में रू. 6,700 करोड़ हो गया है। ये सब विज्ञान प्रसार और शोध को बढ़ावा देने के लिए बढे हुए वित्तीय सहयोग के उदाहरण हैं।

पिछले दशक में ही, कोविड संकट में भारत सरकार द्वारा घोषित 900 करोड़ रुपये के 'मिशन कोविड सुरक्षा' के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने चार टीके वितरित किए। इसरो ने 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 का प्रभावशाली प्रक्षेपण किया है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया है और सफलतापूर्वक आदित्य मिशन लॉन्च

पिछले दस वर्षों में भारत में नवाचार और उद्यमी संस्कृति की एक मज़बूत नींव पड़ी है।

– डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह

किया है जो अंतरिक्ष नवाचार में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाता है।

भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की अपनी वैश्विक रैंकिग में दुनिया की 130 अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्ष 2015 में 81वें से वर्ष 2022 में 40वें स्थान पर भारी छलांग लगाई। हाल में प्रस्तुत हुए अंतरिम बजट में, भारत की नयी उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2023 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक की शुरूआत हुई और अगले पांच वर्षों में विज्ञान, शोध और नवाचार के लिए 50,000 करोड़ के अपव्यय की दूरगामी रूपरेखा तैयार की गयी। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, "एनआरएफ एक दूरगामी लक्ष्य को लेकर की गयी परिकल्पना है जो कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त करेगा"।

हाल के वर्षों में भारत की पेटेंट फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में, इसमें 22 प्रतिशत की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। रेजिडेंट पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत अब विश्व में सातवें स्थान पर है। स्टार्टअप्स की संख्या (77,000) और यूनिकॉर्न की संख्या (107) के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी लेनदेन के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में तीसरे स्थान पर है। मोदी सरकार के तहत भारत ने वित्तीय डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। ये सब टेक्निक और विज्ञान प्रयोग का ही प्रभाव है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वन में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई नए सुधार और प्रयोग किये जा रहे हैं। साथ ही एक ऐसे अकादमिक इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है जहाँ नए–नए व्यवहार और प्रयोगों के द्वारा नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़वा मिले। यह नीति पारंपरिक रूप से रटकर सीखने की पद्धति से हटकर एक ऐसे शैक्षिक दृष्टिकोण पर बल देती है, जो रचनात्मकता, नवाचार, आलोचनात्मक सोच और अंतःविषय शिक्षा को बढ़ावा देता है। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल (आईआईसी) और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान की संस्कृति को स्थापित करने के लिए सरकार के एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अटल इनोवेशन मिशन मोदी सरकार की एक बड़ी लोक नीति है, जिसका लक्ष्य स्कूलों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और सरकारों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत स्कूलों में टिंकरिंग लैब्स, और देश भर में इनोवेशन सेंटरों (स्टार्टअप कॉर्नर) का एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इससे छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव और समस्या–समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसकी स्थापना के बाद से, स्कूलों में 10,000 से अधिक टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

2047 तक आने वाला समय एक ऐसा काल है जो एक मजबूत, आत्मनिर्भर देश के निर्माण के हमारे सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें वैज्ञानिक समुदाय विशेष रूप से हमारे युवा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (फास्ट इंडिया) की ओर से विज्ञान का एक दशकः आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी पैनोरमा शीर्षक से तैयार की गई। रिपोर्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, रक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और भारी उद्योगों जैसे क्षेत्रों में भारत के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के साथ–साथ जिज्ञासा–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी सुधार भी लागू किए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि रिपोर्ट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्षमता निर्माण, ऊर्जा, अन्वेषण, सार्वजनिक सेवा, कृषि, पशु धन और जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य में प्रयासों की जांच की गई।

आज हमें कृत्रिम मेधा, गहरे समुद्र और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में निवेश करना हो, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान–3 की लैंडिंग हो, महामारी के दौरान टीके का विकास या नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की प्रतिबद्धता हो, ये सभी प्रयास आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी निरंतर यात्रा को प्रदर्शित करते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व अनुसंधान किया है, जबकि इसका प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करता है।

ये जरूर है कि आज भारतीय उद्योग द्वारा औसत अनुसंधान एवं विकास खर्च अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिग और गणित (एसटीईएम) में भारतीय महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन पिछले दस वर्षों में भारत में नवाचार और उद्यमी संस्कृति की एक मज़बूत नींव पड़ी है, जो इस ज्ञान–सदी में विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार निश्चय ही इसके लिए बधाई की पात्र है। ❑❑

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।)

विपक्ष की मुफ़्त की गारंटियों के बावजूद एनडीए को बहुमत

2024 का आम चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं की अपेक्षा से कम सीटें पाने में सफल रही, लेकिन एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश ज़रूर मिला है। एक तरफ़ नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए पिछले दस सालों के अपने काम और प्रदर्शन पर वोट मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ़ विपक्षी दलों का 'इंडी' गठबंधन मोदी सरकार के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहा था। एक तरफ़ नरेंद्र मोदी 'जीवन को आसान बनाने' की गारंटी और अपनी नीतियों के साथ लोगों तक पहुँच रहे थे, जिसमें गरीबों के लिए आवास, अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ़्त राशन, गरीबों के साथ–साथ 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत मुफ़्त इलाज, किसान सम्मान निधि और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना शामिल था।

लेकिन कांग्रेस जो कि 'इंडी' गठबंधन की मुख्य पार्टी थी, वह पिछले चुनावों की तरह ही, हर गरीब परिवार को एक लाख रुपए की राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण करके धन का पुनर्वितरण (जनसंख्या के अनुसार) आदि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में थी। इंडी गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल भी मुफ्त योजनाओं का लालच देकर जनता को लुभा रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए वोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत दिलाई। यह साबित करता है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के दस साल के कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीतियों का समर्थन करके एनडीए को विजयी बनाया है, हालांकि उस भारी बहुमत के साथ नहीं, जिसका दावा सत्तारूढ़ गठबंधन कर रहा था, खासकर तीन बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में।

लाभार्थियों का समर्थन

हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, जिनके लाभार्थियों ने स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया

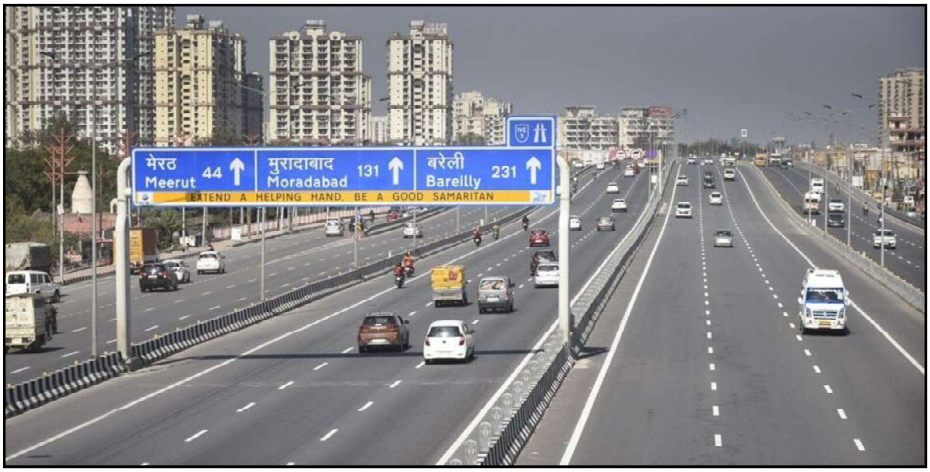

आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके।
– स्वदेशी संवाद

है। लाभार्थियों की बात करें तो 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण, नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। गौरतलब है कि जो गरीब परिवार पहले कच्चे या अर्ध–कच्चे मकानों में रहते थे, उनके लिए पिछले कुछ सालों में करीब 3 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी मकान बनाए गए। अगर पांच लोगों के परिवार को माना जाए तो करीब 20 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी रहे हैं। समझा जा सकता है कि इस योजना ने उन गरीब परिवारों की कुशलता और जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाया है। स्वाभाविक रूप से एनडीए को इन लाभार्थियों का समर्थन मिला है। इसके साथ ही गरीबी के कारण एलपीजी कनेक्शन से वंचित 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन लाभार्थियों ने भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन किया है।

वैसे तो महिला स्वाभिमान के प्रतीक शौचालयों के निर्माण को सामाजिक क्रांति माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस योजना के कारण खुले में शौच से मुक्त हुई महिलाओं का समर्थन भी मौजूदा सरकार चला रही पार्टियों को मिला होगा। लगभग पूरे देश को नल से जल और शत–प्रतिशत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना किसी क्रांति से कम नहीं माना जा सकता। करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन और किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की राशि जारी रखने की गारंटी भी एक लोकप्रिय कदम माना जा रहा है। समझना होगा कि किसान सम्मान निधि को छोड़कर, जिसका असर करीब 75000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष सरकारी खर्च पर पड़ता है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी अन्य योजना नकद वितरण वाली नहीं थी।

कांग्रेस की नकद वितरण योजना कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाई

इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे और 2024 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था और तब भी कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 52 सीटें ही मिलीं। यानी तब भी लोगों ने कांग्रेस की नकद वितरण योजना को नकार दिया था। इस बार कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हर गरीब परिवार को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा किया था और इसका खूब प्रचार भी किया था। हालांकि, कांग्रेस के इस वादे के क्रियान्वयन को लेकर लोगों में काफी संदेह था और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर, सरकार में शामिल होने के लिए जादुई संख्या से काफी कम 100 से कुछ कम ही रहीं।

एक तरफ जनता द्वारा नकद वितरण योजना को नकारना और दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिखाया जा रहा भरोसा, देश के मतदाताओं और लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

नई सरकार की क्या होंगी प्राथमिकताएं?

देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। यह सच है कि पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है और देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता अभी भी बनी हुई है। हालांकि, अत्यधिक गरीबी में काफी कमी आई है; लेकिन मोदी सरकार के पहले नौ वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के बावजूद बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ष 2023 तक 12 करोड़ बनी हुई थी। यह सही है कि राजकोषीय सूझबूझ के कारण सरकार का पूंजी निवेश बढ़ रहा है, देश में बड़ी मात्रा में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है, जिससे देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में सफलता मिल रही है। दूसरी ओर, तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन लेन–देन दुनिया में कहीं और की तुलना में भारत में कहीं अधिक हो रहा है, सरकार अधिक से अधिक पेटेंट देने में भी सफल रही है; और अंततः वर्ष 2014 में केवल 4227 पेटेंट की तुलना में वर्ष 2024 में 1.03 लाख पेटेंट दिये गए, जो देश में नवाचार में विकास को दर्शाता है। हालाँकि, उत्पादों के निर्माण में हमारी निर्भरता अभी भी विदेशों पर बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। देश में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे। यह सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मशीनों और एआई का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में कम हो, जहां श्रम का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही, ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों को विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। ❑❑

क्या भारत कभी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा?

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार श्री एंग्स मेडिसिन के अनुसार वर्ष 1820 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, 1820 आते–आते चीन भारत से आगे निकल गया था। 1820 से 1870 के बीच चीन एवं भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पूरे विश्व में सबसे आगे थे। वर्ष 1870 से 1900 के बीच ब्रिटेन विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया, परंतु ब्रिटेन पर यह ताज अधिक समय तक नहीं टिक सका, क्योंकि इसके तुरंत बाद अमेरिका विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया था। इसके बाद तो आर्थिक प्रगति के मामले में अमेरिका एवं यूरोपियन देश लगातार आगे बढ़ते रहे, विकसित अर्थव्यवस्थाएं बने और एशिया के देशों (विशेष रूप से भारत एवं चीन) का वर्चस्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग समाप्त सा हो गया था। परंतु, अब एक बार पुनः समय चक्र बदल रहा है एवं अमेरिका एवं यूरोपियन देशों की अर्थव्यस्थाएं आर्थिक विकास के मामले में ढ़लान पर दिखाई दे रही हैं एवं एशिया के देश, विशेष रूप से भारत एवं चीन, पुनः तेज गति से आर्थिक प्रगति करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम करते नजर आ रहे हैं।

आज अमेरिकी अर्थव्यस्था का आकार लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है और चीन की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 18 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2035 से 2040 के बीच चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं अमेरिका दूसरे नंबर पर आ जाएगा और भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा। परंतु, इसके बाद क्या भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ पाएगा। इस तरह की चर्चाएं आजकल आर्थिक जगत में होने लगी हैं। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 11वां स्थान था जो आज 3.70 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के आकार के साथ विश्व में 5वें स्थान पर आ गई है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर विश्व में चौथे स्थान पर आ जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2027 में जापानी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगी। गोल्ड्मन सच्स के अनुसार, अगले चार वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार, ब्लूम्बर्ग के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था आगामी वर्षों में लगातार 6 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल करता रहेगा, और अमेरिका एवं चीन की आर्थिक विकास दर से आगे बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के तेज गति से आगे रहने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं – भारतीय जनसंख्या में वृद्धि होते रहना (अमेरिका एवं चीन में जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम हो रही है), इससे भारतीय घरेलू बाजार मजबूत बना रहेगा एवं उत्पादों की मांग भी भारत में तेज गति से आगे बढ़ती रहेगी। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की आबादी बढ़ कर 170 करोड़ नागरिकों की हो जाएगी, इससे भारत अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।

वर्ष 2024 में भारत में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक 98.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। दूसरे, भारत में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए भी केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक

आगे आने वाले कालचक्र में वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में परिस्थितियां लगातार भारत के पक्ष में होती दिखाई दे रही हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगातार बढ़ते जाने की प्रबल संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं।

–प्रहलाद सबनानी

मात्रा में पूंजी निवेश किया जा रहा है। भारत में आधारभूत ढांचे को विकसित श्रेणी में लाने के लिए केवल रोड ही नहीं बल्कि रेल्वे, एयरपोर्ट, ऊर्जा एवं जल व्यवस्था को विकसित करने के लिए भी भरपूर पूंजी निवेश किया जा रहा है।

भारत में आज भी श्रमिक लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, इससे कई विदेशी कंपनियां अब चीन के स्थान पर भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयों को स्थापित कर रही हैं इससे भारत के औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। भारत ने भी कई उद्योग क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसका लाभ विश्व की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठा रही हैं एवं अपनी औद्योगिक इकाईयां भारत में स्थापित कर रही हैं।

तीसरे, भारत में आज 140 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ से अधिक नागरिक युवा एवं कार्य कर सकने वाले नागरिकों की श्रेणी में शामिल हैं। इतनी बड़ी मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धि किसी भी अन्य देश में नहीं है। अन्य विकसित देशों, चीन सहित, में कार्य कर सकने वाले नागरिकों की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी भी देश में युवा जनसंख्या का अधिक होने से न केवल श्रमिक के रूप में इनकी उपलब्धि आसान बनी रहती है बल्कि इनके माध्यम से देश में उत्पादों की मांग में भी वृद्धि दर्ज होती है तथा युवा जनसंख्या की उत्पादकता भी अधिक होती है जिससे उत्पादन लागत कम हो सकती है। साथ ही, युवाओं द्वारा नवाचार भी अधिक मात्रा में किया जा सकता है। यह सब कारण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में एक चमकता सितारा बनाने में सहायक हो रहे हैं।

हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से

भारत आज अमेरिका, चीन, जर्मनी एवं जापान के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही, भारत आज पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

बदला भी है। अभी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकसित देशों का दबदबा बना रहता आया है। परंतु, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत सहित एशियाई देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत का योगदान होने की प्रबल संभावना बन रही है। एशियाई देशों में चीन एवं भारत मुख्य भूमिकाएं निभाते नजर आ रहे हैं। प्राचीन काल में वैश्विक अर्थव्यस्था में भारत का योगदान लगभग 32 प्रतिशत से भी अधिक रहता आया है। वर्ष 1947 में जब भारत ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय वैश्विक अर्थव्यस्था में भारत का योगदान लगभग 3 प्रतिशत तक नीचे पहुंच गया था क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले अरब से आए आक्राताओं एवं बाद में अंग्रेजों ने बहुत नुक्सान पहुंचाया था एवं भारत को जमकर लूटा था। वर्ष 1947 के बाद के लगभग 70 वर्षों में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान में कुछ बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आ पाया था। परंतु, पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में लगातार मजबूत होते लोकतंत्र के चलते एवं आर्थिक क्षेत्र में लिए गए कई पारदर्शी निर्णयों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को तो जैसे पंख लग गए हैं। आज भारत इस स्थिति में पहुंच गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024 में अपने योगदान को लगभग 18 प्रतिशत के आसपास एवं एशिया के अन्य देशों यथा चीन, जापान एवं अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशियाई देशों के योगदान को 60 प्रतिशत तक ले जाने में सफल होता दिखाई दे रहा है।

भारत आज अमेरिका, चीन, जर्मनी एवं जापान के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ ही, भारत आज पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में तो भारत की आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत की रही है और यह वित्तीय वर्ष 2023–24 की समस्त तिमाहियों में लगातार तेज गति से बढ़ती रही है। पहली तीन तिमाहियों में भारत की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक रही है, अक्टूबर–दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में तो आर्थिक विकास दर 8.4 प्रतिशत की रही है। इस विकास दर के साथ भारत के वर्ष 2025 तक जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है। केवल 10 वर्ष पूर्व ही भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और वर्ष 2013 में मोर्गन स्टैनली द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत विश्व के उन 5 बड़े देशों (दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, टर्की एवं भारत) में शामिल था जिनकी अर्थव्यवस्थाएं नाजुक हालत में मानी जाती थीं। अब आगे आने वाले कालचक्र में वैश्विक स्तर पर आर्थिक क्षेत्र में परिस्थितियां लगातार भारत के पक्ष में होती दिखाई दे रही हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान लगातार बढ़ते जाने की प्रबल संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। ❑❑

कृषि बजट वृद्धि दिलाएगी 'अरबपति राज' से मुक्ति

भले ही वह विशुद्ध राजनीतिक कारणों से हो, भारत में धन के पुनः बंटवारे पर बहस बेहद महत्वपूर्ण है और वक्त की जरूरत भी। मुट्ठीभर अमीरों के हाथों में धन के केंद्रित होने की अप्रिय स्थिति की वजह से 'अरबपति राज का उदय' हुआ, जैसा कि पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब ने इसे नाम दिया है। यह कथित 'अरबपति राज' निश्चित रूप से उद्यमशीलता के प्रति एनिमल स्पिरिट यानी जिंदादिली या भावनात्मक जोश के उजागर होने के कारण नहीं है लेकिन यह इस बात का दुखद परिदृश्य है कि कैसे कुछ लोगों के हक में आर्थिक नीतियों और संसाधनों को अनावश्यक रूप से सौंप दिया गया।

जॉन मेनार्ड केंज ने अपनी पुस्तक 'द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी' (1936) में 'एनिमल स्पिरिट्स' की व्याख्या उस असाधारण मानवीय व्यवहार के रूप में की है जो अनिश्चयपूर्ण दशाओं में निवेशकों को वित्तीय निर्णय लेने को प्रेरित करता है। पर संभवतया केंज को यह अहसास नहीं हो कि बहुसंख्यक आबादी को ऐसे ही अवसर से वंचित रखना असल में लाखों फूलों के खिलने के लिए जरूरी उत्साह और 'एनिमल स्पिरिट' को नष्ट करना है। किसी भी मामले में, जहां केंज गलती पर हैं, वह यह है कि मुट्ठी भर अरबपतियों का होना महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी संपत्ति एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई उस मददगार प्रणाली के बल पर बढ़ती रहती है, जिसमें टैक्स छूट, बैंक ऋण बट्टे खाते में डालना और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। बल्कि उसी के समान संसाधनों को एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए भी खर्च करना होगा जहां खुशी और संतुष्टि का राज हो। आख़रिकार, संसाधन सीमित हैं और यह देखना अहम है कि इन्हें कैसे वितरित किया जाता है। शायद यही वजह है कि नॉर्डिक क्षेत्र के 4 देशों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड बेहद अच्छा कर रहे हैं और खुशहाली की सूची में लगातार अव्वल रहते हैं।

एक दिन टीवी पर पैनल चर्चा के दौरान मुझसे पूछा गया कि यदि धन का पुनः वितरण करना पड़ा तो सरकार क्या कर सकती है। मेरा जवाब था कि लगता नहीं है कि अमीरों का धन छीनकर गरीबों में बांटने का कोई विचार हो। चाहिये क्या कि नीतियों और दृष्टिकोणों में पुनः बदलाव कर यह यकीनी बनाना होगा कि उनका लाभ देश के किसी भी हिस्से में मौजूद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

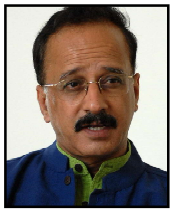

कृषि क्षेत्र में आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि उचित निवेश नहीं करते।

– देविन्दर शर्मा

मेरा पहला सुझाव होगा यह यकीनी बनाना कि सालाना बजट का 50 फीसदी कृषि को दिया जाना चाहिये जो साल 2024 के लिए 47.66 लाख करोड़ है। जो मोटेतौर पर देश की आधी आबादी बनती है। खेती में आबादी का इतना बड़ा हिस्सा लगे होने के बावजूद वर्तमान में इस क्षेत्र को बजट आवंटन में 3 फीसदी से भी कम प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि उचित निवेश नहीं करते।

ऐसे देश में जहां सिर्फ 21 अरबपतियों के पास 700 मिलियन से अधिक की धन–संपत्ति है, और जहां 64.3 प्रतिशत आबादी से 64.3 प्रतिशत जीएसटी आता है और शीर्ष 10 फीसदी से केवल 3–4 प्रतिशत ही आता है। जहां पहले से ही काफी निवेश किया जा चुका हो, वहां संसाधनों को लगाने में कोई आर्थिक समझदारी नहीं। इसके विपरीत, वित्तीय संसाधनों का समान और न्यायसंगत तरीके से पुनर्वितरण करना नितांत आवश्यक है। खेती में लगी 50 फीसदी आबादी को आर्थिक संसाधनों में उसके जायज हिस्से से क्यों वंचित किया जाए,

जबकि लगातार सरकारें साल–दर–साल औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर बजटीय प्रावधान करती रही हैं।

मुझसे सवाल किया गया कि खेती से आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, और वह इस सेक्टर के लिए बड़ी वित्तीय मदद है। वास्तव में, पैनल चर्चा में शामिल एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने यहां तक पूछा कि अमीर किसानों पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, जबकि उन्हें यह अहसास नहीं था कि भारत में केवल 1 प्रतिशत कृषक समुदाय के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और कृषक परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण, 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शेष 99 प्रतिशत कृषक समुदाय की औसत आय लगभग 10,000 रुपये प्रति माह है। विडंबना है कि कॉर्पोरेट अर्थशास्त्रियों को कृषि क्षेत्र में व्याप्त संकट के बारे में बहुत कम जानकारी है, और वे अभी भी पुराने जमाने की आर्थिक सोच पर चलते हैं जो किसानों को शहरों में प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर आधारित थी।

भारत में केवल 1 प्रतिशत कृषक समुदाय के पास ही 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और कृषक परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण, 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शेष 99 प्रतिशत कृषक समुदाय की औसत आय लगभग 10,000 रुपये प्रति माह है।

एक अन्य पैनल चर्चा में, मैंने बताया कि कैसे कॉर्पोरेट कंपनियां पिछले दस वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये के बैंक राइट–ऑफ लेकर गयी हैं, और इसके साथ सितंबर 2019 से हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये की टैक्स कटौती दी गई है। इतना कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के साथ 'समझौता' करने का निर्देश दिया है, जिन पर 3.45 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, और जिनके पास भुगतान करने के लिए संसाधन हैं लेकिन वे परवाह नहीं करते हैं। जिस तरह से किसानों को बैंक की किस्तें चुकाने में असमर्थ होने के चलते जेल में डाल दिया जाता है, उसी तरह 16,400 जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को भी जेल की सजा होनी चाहिए थी। इसके बजाय उन्हें आसानी से छोड़ दिया गया। इस तरह के भारी राइट–ऑफ से अमीरों को जाहिर तौर पर राहत मिलती है। उनकी जीवनशैली हमेशा पूर्ववत चलती रहती है। यदि किसानों को भी ऐसी राहत राशि दी जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे भी अपनी 'एनिमल स्पिरिट' का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।

मई 1996 में जब वाजपेयी सरकार ने पहली बार शपथ ली, तब नई सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले आर्थिक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए बुलाई गई अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में मेरा सुझाव था कि कृषि में संलग्न 60 प्रतिशत आबादी के लिए वार्षिक बजट का 60 प्रतिशत प्रदान किया जाए, यदि विचार सत्ता विरोधी लहर से बचने का हो। (उस समय जनसंख्या का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि का था)। यह बात अब भले ही भुला दी गई हो लेकिन वाजपेयी सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए समर्पित करेगी। यह एक ऐसा परिवर्तनकारी कदम होता जिसकी देश को तलाश थी। जहां तक मुझे याद है यह पहली बार था कि संसाधनों के पुनर्वितरण का प्रयास किया गया था। दुर्भाग्य से, सरकार 13 दिन में ही गिर गयी। यदि केवल वाजपेयी सरकार कायम रहती, कृषि पर बजट आवंटन में 60 फीसदी लगाने के नीतिगत फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था यकीनी तौर पर पुनर्जीवित होती और उसके असर से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी आती। उसके चलते अब तक सबका साथ सबका विकास यकीनी बनता।

अब जबकि नव–उदारवाद हांफ रहा है और अपने अंतिम चरण में है, ऐसे में धन के पुनः वितरण की किसी भी बात को अर्थशास्त्रियों के शासक वर्ग के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनसे घबराएं नहीं, बल्कि खड़े हो जाओ और अपनी राय से अवगत कराएं। और विश्वास रखें कि धन का पुनः वितरण एक विचार है जिसका समय अब आ गया है। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/increasing-the-agriculture-budget-will-bring-freedom-from-the-billionaire-rule/

सोना क्यों बन रहा है पहली पसंद?

पहले विश्व युद्ध के बाद से अब तक दुनिया में डॉलर का महत्व लगातार बढ़ता रहा है। जब अमरीका के सहयोगी देश सामान के बदले सोना देने लगे, तो ऐसे में संयुक्त राज्य अमरीका अधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बन गया। युद्ध के बाद अनेक देशों ने अपनी कैरेंसियों को डॉलर के साथ जोड़ा और इसके साथ ही दुनिया में गोल्ड स्टेण्डर्ड समाप्त हो गया और डॉलर दुनिया की सबसे पसंदीदा कैरेंसी बन गई। सभी देशों ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडारों को डॉलर के रूप में रखना शुरू कर दिया, और ऐसे में वर्ष 1999 तक दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर का हिस्सा 71 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1999 में यूरोप साझा कैरेंसी यूरो का प्रादुर्भाव हुआ और अब अधिकांश यूरोपीय देशों ने डॉलर के बदले यूरो रखना शुरू कर दिया। इसके चलते रिजर्व कैरेंसी के नाते डॉलर का हिस्सा घटने लगा और वर्ष 2021 तक यह घटकर 59 प्रतिशत रह गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार डॉलर का वैश्विक रिजर्व कैरेंसी के रूप में हिस्सा 2010 में 62 प्रतिशत, 2015 में 65.73 प्रतिशत, 2020 में 59 प्रतिशत और 2023 में 58.41 प्रतिशत रह गया। समझना होगा कि उतार–चढ़ाव के साथ वर्ष 1999 से डॉलर का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व कैरेंसी के नाते लगातार घटता रहा है।

लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे डॉलर का महत्व घटता गया हो, लेकिन डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे अधिक पसंदीदा कैरेंसी बना हुआ है। उसके मुकाबले दूसरे स्थान पर यूरो का हिस्सा अभी भी 20 प्रतिशत के आसपास ही है, और बाकी कोई भी कैरेंसी उसके नजदीक भी नहीं है। आज भी दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन डॉलर में होते हैं। इस कारण से डॉलर लंबे समय से कभी भी खास कमजोर नहीं हुआ। भारतीय रूपए के संदर्भ में देखें तो 1964 में जहां एक डॉलर 4.66 रूपए के बराबर था, वो अब बढ़कर 83.4 रुपए तक पहुंच चुका है। अन्य कैरेंसियों की तुलना में भी यह काफी मजबूत रहा है।

लेकिन कुछ समय से दुनिया के देशों में वि–डॉलरीकरण के संकेत मिल रहे हैं। डॉलर के लगातार मजबूत होने के कारण लगभग सभी देशों, खासतौर पर विकासशील देशों को

सोने की बढ़ती यह मांग, कई सवाल खड़े करती है, उसमें से सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अब डॉलर का वर्चस्व समाप्त हो रहा है।
–स्वदेशी संवाद

खासा नुकसान होता रहा है। भारत की यदि बात करें तो पिछले कुछ समय से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में रूपए की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहा है। लगभग 20 देशों के साथ इस बाबत सहमति भी बनी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय उथल–पुथल और खासतौर पर रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में कठिनाई के कारण, दूसरे देशों में भी स्थानीय कैरेंसियों में भुगतान के प्रयास तेज हो गए हैं।

दुनिया में डॉलर के प्रति विमुखता इस कारण से भी बढ़ी है, क्योंकि अमरीका ने रूस को आक्रमणकारी बताते हुए उसके तमाम डॉलर रिजर्व को जब्त कर लिया है। ऐसे में दूसरे मुल्कों में यह भय व्याप्त हो गया है कि देर–सबेर अमरीका ऐसी कारवाई उन पर भी कर सकता है। ऐसे में उन मुल्कों पर रूस जैसी भुगतान की समस्या आ सकती है। ऐसे में दुनिया के मुल्क दो तरफा प्रयास कर रहे हैं। एक, स्थानीय कैरेंसियों में भुगतान तो दूसरा डॉलर के स्थान पर सोने के भंडार में वृद्धि।

भारत की यदि बात करें तो देखते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते–बढ़ते अप्रैल के पहले सप्ताह तक 648.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन इस बीच में एक और महत्वपूर्ण बात जो दिखाई दी कि विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने का भंडार 55.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें एक ही सप्ताह में 1.24 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। बताया जा रहा है कि एक ही सप्ताह में सोने के भंडार में 6 टन वृद्धि हुई। पिछले साल की तुलना में भारत का स्वर्ण भंडार 13 टन ज्यादा है। दुनिया में अधिकारिक स्वर्ण भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान 9वां है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार की प्राथमिकता के बारे में आधिकारिक पुष्टि भी की है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जहां विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा 450.1 टन सोने की खरीद की गई, वो बढ़कर 2022 में 1135.7 टन हो गई। वर्ष 2023 में केन्द्रीय बैंकों ने 1037 टन सोने की खरीद की। गौरतलब है कि गहनों के रूप में सोने की मांग पहले के मुकाबले में लगातार घटती जा रही है, जबकि निवेश के रूप में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच पिछले सालों में केन्द्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि ने दुनिया में सोने की मांग बढ़ा दी है। यदि सोने के भाव की बात करें तो पिछले दो–तीन वर्षों में सोने की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

वर्ष 2018 में सोने की औसत कीमत 1268.93 डॉलर प्रति ओंस थी, जो वर्ष 2024 में अभी तक 2126.82 डॉलर प्रति ओंस तक पहुंच चुकी है। यानि मात्र 6 वर्षों से भी कम समय में सोने की कीमत में 67.6 प्रतिशत की वृद्धि, यानि लगभग 9.5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि।

क्यों बढ़ रही है सोने की पसंद?

यह बात सर्वथा सिद्ध हो रही है कि दुनिया में सोने की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 1988 में सोने की कीमत 437 डॉलर प्रति आउंस थी, जो 2018 तक बढ़कर 1268.93 तक पहुंची थी, यानि 30 सालों में 3.61 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि। लेकिन पिछले 6 सालों में सोने की कीमतें 9.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं। ऐसे में दुनिया के आर्थिक विश्लेषक, वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इंगित कर रहे हैं।

पहला कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर, जिसे फेड रेट भी कहते हैं, उसके घटने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे में चूंकि ब्याज दरें कम होने पर लोग वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय सोना खरीदने की ओर आकर्षित होंगे। ऐसे में यदि ब्याज दर गिरती है तो सोने की मांग बढ़ेगी।

दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि चीन समेत दुनिया भर के केन्द्रीय बैंक अब ज्यादा से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इस प्रवृत्ति के थमने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही।

तीसरा दुनिया भर में सोने की कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। ऐसे में केन्द्रीय बैंकों द्वारा ज्यादा सोना खरीदने की संभावनाएं और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यदि केन्द्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में सोने की मात्रा बढ़ाते है, तो बढ़ती सोने की कीमतों के साथ उनके विदेशी मुद्रा भंडार स्वयमेव बढ़ जाएंगे।

सोने की बढ़ती यह मांग, कई सवाल खड़े करती है, उसमें से सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अब डॉलर का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। एक दूसरा सवाल यह है कि क्या सोने का महत्व अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में भी बढ़ने वाला है। क्या ऐसा होगा या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि विश्व वि–डॉलरीकरण की ओर बढ़ रहा है, तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ देश अपने विदेशी व्यापार को अपनी घरेलू मुद्राओं में निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में डॉलर के विकल्प में सर्वाधिक प्राथमिकता सोने को दी जा सकती है। दुनिया के कई देश अमरीका द्वारा उनके विदेशी भंडारों के ज़ब्त होने के अंदेशे से भी आशंकित हैं, क्योंकि रुस के साथ अमरीका ऐसा कर चुका है। भारत और चीन सहित दुनिया में सोने की माँग बढ़ने का यह भी एक मुख्य कारण बन रहा है। ❑❑

भारत के बाहर भारतीयता

विश्व भर में सनातन धर्म की विशालता और हिंदुओं का प्रभाव बहुत प्रेरणादायक विषय तो है ही, परंतु इस को भारत से बाहर देखने से यथार्थ और इसका वृहद रूप समझ आता है। जो कुछ हम इस विषय को भारत में पढ़ने और शोध करने से प्राप्त करते हैं, वह विशुद्ध रूप से शैक्षणिक महत्व का ही रहता है। यदि विदेशी धरती से इसको देखा और समझा जाये तो उसमें बहुत जिज्ञासा से परिपूर्ण, गहरी समझ और हृदयस्पर्शी ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में भी सनातन के स्वरूप में बहुत विविधता है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं में विविधता के बावजूद एकरूपता है। विभिन्न देशों में सदियों और पीढ़ी दर पीढ़ी से बसे भारतीय मूल के निवासियों का धार्मिक और सामाजिक स्वरूप बदल चुका है फिर भी भारतीयता पूर्णतः परिलक्षित होती है।

28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख पत्रिका ऑर्गेनाइजर में "ट्रेसिंग फिलियल लिंक्स" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ था जो आस्ट्रेलिया के वनवासियों (एबॉरिजिंस) के मूल भारतीय होने के वैज्ञानिक अध्ययन और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था और एबॉरिजिनल लेखक अंकल ग्राहम पॉलसन के आस्ट्रेलियाई वनवासियों की आध्यात्मिकता पर लेखों से उद्धृत था। इस लेख में उनका डीएनए भारतीयों के डीएनए का 11 प्रतिशत बताया गया। भारत से 14000 किमी दूर आस्ट्रेलियाई जनमानस की मुख्यधारा से बाहर और दूरदराज के जंगलों में बसे इन वनवासियों का भारतीय मूल से जुड़ा होना बहुत असंभव सा प्रतीत होता था। समय–समय पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आस्ट्रेलियाई एबॉरिजिंनल्स पर लेख प्रकाशित होते रहे जिनमें वह सैकड़ों वर्षों पूर्व के रहन सहन, वेश–भूषा, खान–पान और मान्यताओं में दिखाए गये। कई अन्य वैज्ञानिक और मेडिकल शोध में आस्ट्रेलियाई एबॉरिजिंनल्स को 50000 वर्षों पूर्व भारत से आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में प्रवर्जित बताए गये और पापुआ न्यू गिनी के वनवासियों के समान कहा गया।

भारत से बाहर भारतीयता का वर्णन करना लगभग असंभव है। भारत से बाहर जाकर इतना विश्वास रहता है कि एक विशाल भारत विदेशों में भी है।

–विनोद जौहरी

सौभाग्य से मेरा आस्ट्रेलिया जाना होता है और वहां एक दो माह का निवास भी होता है, जिसमें विक्टोरिया (मेलबर्न), वेस्ट आस्ट्रेलिया (माउंट गैंबियर) और न्यू साउथ वेल्स (सिडनी) में जाना हुआ। सिडनी से ब्लू माउंटेन जाते समय सिडनी से लगभग 100 किमी दूर एक छोटा शहर है कुटूंबा जो जिला मुख्यालय भी है। कुटूंबा में एक पर्वतीय एबॉरिजिनल साइट है जो बहुत विशाल साइट है और दूर दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियां फैली हुई हैं जिनके बीच एक कडूंबा नदी भी थी जिसके किनारे–किनारे वनवासियों का वास था। वहां एक शिलालेख भी है जिसमें वनवासियों के इतिहास के बारे में लिखा है। कटूम्बा ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन शहर का मुख्य शहर और ब्लू माउंटेन सिटी काउंसिल का प्रशासनिक मुख्यालय है। कटूम्बा, धारुग और गुंडुंगुर्रा आदिवासी लोगों की भूमि पर स्थित है। ब्लू माउंटेन एक बहुत ही सुन्दर पर्यटक पर्वतीय स्थान है जहां तीन दिन ठहरे। अब इस साइट पर कोई एबॉरिजिंनल्स नहीं रहते। ऐसा माना जाता है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा इन एबॉरिजिंनल्स का बड़ी संख्या में नरसंहार किया गया।

ऐसा नहीं है कि एबॉरिजिंनल्स दिखाई नहीं देते। न्यू साउथ वेल्स में नदियों के आसपास यह बैठे दिखाई देते हैं और बहुत से सिडनी में भी बस गये हैं। जैसा आस्ट्रेलियाई वनवासियों को लेखों में आदिवासी रूप में दिखाया जाता है, वैसे नहीं हैं। भारतीयों से रंग

रूप, बनावट, हाव–भाव में हम जैसे ही हैं। आस्ट्रेलिया में वह अब भी मुख्यधारा में नहीं हैं और जीवनयापन के लिए संघर्षरत हैं। जो एबॉरिजिंस शहर या कस्बों में आ गये हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं जब अपने नाती–नातिन (बेटी के पुत्र और पुत्री) को सिडनी के केंसिंग्टन पब्लिक स्कूल में प्रातः छोड़ने जाता था तो बहुत से ब्रिटिश, चीनी, श्रीलंकाई, पाकिस्तानी और विभिन्न देशों के प्रवर्जित नागरिकों के बच्चे भी स्कूल में आते थे। तो कुछ बिल्कुल भारतीय दिखने वाले बच्चों के बारे में अपनी बेटी से पूछा तो पता चला कि वह एबॉरिजिंनल्स बच्चे हैं। बिल्कुल हमारे जैसे। युवा और वयोवृद्ध एबॉरिजिंनल्स जैसे पंजाब के किसी पिंड से हों। वैसी ही बलिष्ठ बनावट। रंग थोड़ा सांवला, थोड़े से घुंघराले बाल।

असली बात यह है कि वे आस्ट्रेलिया के मूल नागरिक हैं। विदेशी आक्रांता आस्ट्रेलिया में ही बस गये जैसे हमारे देश से ब्रिटिश आक्रांता वापस इंग्लैंड चले गये।

आस्ट्रेलिया, यूरोपीय और अन्य देशों में भारतीय, श्रीलंकाई, नेपाली, सूरीनाम, पाकिस्तानी, बंग्लादेशी, इराकी, थाई, फिजी, तिब्बती, मलेशियाई, मॉरिशस, इंडोनेशियाई सब एक जैसे लगते हैं। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अपने को "इंडियन" बोलते हैं और विभाजन से पूर्व प्रवासित बताते हैं। यदि भारतायों से मिलना हो तो इस्कॉन व अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में भारतीयों का जाना होता है। पीढ़ियों से बसे भारतीय भी बड़े–बड़े व्यापार में समृद्ध हैं। जो भारतीय नौकरियों के बजाय व्यापार में लगे वह समृद्ध हैं। विदेशों में विभिन्न एअरपोर्ट पर भारतीय, मॉरिशस, सूरीनाम, फ़िजी मूल के कर्मचारी मिल जाते हैं और हमको भारतीय जानकर बहुत सहायता और अच्छा व्यवहार करते हैं। हिंदी समझते हैं और बात भी करते हैं। भारतीय खाद्य पदार्थों, पूजा अर्चना का सामान बड़े आराम से भारतीय और नेपाली दुकानों पर मिलता है। सागर रत्ना जैसे रेस्टोरेंट भी भारतीयों से मिलने के सुअवसर हैं। बड़े मॉल में भी भारतीय वस्तुएं, हल्दीराम के खाद्य पदार्थ सुलभ हैं। घर में कोई पूजा पाठ कराना हो तो फिज़ी और मॉरिशस के कर्मकाण्ड के पंडितजी मिल जाते हैं जो स्थानीय प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन हैं। भारतीयों के बिना विदेश भी सूने हैं क्योंकि मातृभूमि से प्रेम करना उनके डीएनए में हैं। आज भारतीय मूल के विभिन्न देशों में 200 सांसद और 60 राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री हैं।

भारत से बाहर भारतीयता का वर्णन करना लगभग असंभव है। भारत से बाहर जाकर इतना विश्वास रहता है कि एक विशाल भारत विदेशों में भी है। जितना देखा, उतना लिखा। जितना पढ़ा उसको व्यवहारिकता पर परखा। ❑❑

(आस्ट्रेलिया से लौटकर)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)**
में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जल संकट

जल के छल का कैसे हो हल?

जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले के आरोप में कैद हैं। दिल्ली की आम जनता पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रही है और बाल्टी लेकर टैंकरों के पीछे भाग रही है। सरकारी अमला–जमला पड़ोसी राज्यों पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। अदालतें आए दिन नसीहतें दे रही हैं। लगातार बढ़ते तापमान के साथ जी रहे मजबूर लोगों के लिए जरूरी पानी के धधकते सवाल पर कोई ठोस हल के साथ आगे आने के बजाय दिल्ली की जनता को आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के जबाव में जितने मुंह उतनी बातें हो रही है।

इस बार गर्मी तीखी है और इसके लंबा चलने की बात हो रही है। ऐसे में पानी की मांग बढ़ना लाजिमी है। बीते आठ वर्षों की तरह दिल्ली की सरकार का जल आपूर्ति में कमी के लिए हरियाणा को कोसना और फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना इस बार भी जारी रहा। इस बार यह तथ्य उभर कर आया कि राजधानी में पानी की उतनी कमी नहीं है, जितनी उसके प्रबंधन की। भारत सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने जब इस बात के दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए कि दिल्ली को मिल रहे पानी की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है तो अदालत ने भी इसे गंभीराा से लिया। मेहता ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि दिल्ली को मिलने वाले प्रत्येक 100 लीटर पानी में से केवल 48.65 लीटर पानी ही लोगों तक पहुंच पाता है। इसका 52.35 प्रतिशत हिस्सा, रिसाव, टैंकर माफिया और औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी का शिकार है।

राजधानी दिल्ली में इस बार पूरी गर्मी जल संकट स्थाई रूप से डेरा डाले रहा। सरकारी अनुमान है कि दिल्ली की आबादी तीन करोड़ चालीस लाख के करीब पहुंच गई है और यहां हर दिन पानी की मांग प्रतिदिन 1290 मिलियन गेलन (एमएलडी) है जबकि उपलब्ध पानी महज 900 एमएलडी है। इसमें से लगभग आधे पानी का जरिया यमुना ही

बीते आठ वर्षों की तरह दिल्ली की सरकार का जल आपूर्ति में कमी के लिए हरियाणा को कोसना और फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना इस बार भी जारी है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

है, शेष जल ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा बांध आदि से आता है। दिल्ली के 9 में से 7 जल शोधन संयत्र तभी काम करते हैं जब उन्हें मुनक नहर से यमुना का पानी मिले।

मुनक नहर का निर्माण 2003 और 2012 के बीच हरियाणा सरकार ने किया था। यह करनाल जिले में यमुना का पानी लेकर खूबरू और मंडोरा बैराज से होकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। करनाल के मुनक गांव से दिल्ली के हैदरपुर तक नहर 102 किमी लंबी है और यह दिल्ली में महज 16 किलोमीटर का ही सफर करती है।

विदित हो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यमुना जल के बंटवारे के समझौते के ठीक से पालन हेतु गठित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के विशेषज्ञों का एक दल पिछले 10 जून को नहर के निरीक्षण पर गया था। इनकी रिपोर्ट है कि हरियाणा से तो पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचते–पहुंचते उसका बड़ा हिस्सा गुम जा रहा है। जैसे कि हरियाणा ने मूनक नहर में 2,289 क्यूसेक पानी छोड़ा। काकोरी से भी निर्धारित मात्रा 1050 क्यूसेक की तुलना में 1161.084 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। काकोरी वह जगह है, जहां से पानी सीधे दिल्ली पहुंचता है, लेकिन 16 किलोमीटर के रास्ते चलकर बवाना में मूनक नहर को 960.78 क्यूसेक पानी ही पहुंचा। जाहिर है कि लगभग 200 क्यूसेक पानी बीच में ही गायब हो गया। नियमानुसार इस तरह के प्रवाह में पांच फीसद तक जल की क्षति हो सकती है, लेकिन यहां तो 18 प्रतिशत पानी कम हो गया।

आखिर जल प्रबंधन में दिल्ली का प्रशासन किस तरह पीछे है? इसकी बानगी है वजीराबाद जल शोधन संयत्र। वजीराबाद बैराज के पास बने जलाशय से यह पानी लेता है। पहले जलाशय की गहराई हुआ करती थी 4.26 मीटर, इसकी गाद को किसी ने साफ करने की सोची नहीं और अब इसमें महज एक मीटर से भी कम 0.42 मीटर जल–भराव क्षमता रह गई। तभी 134 एमजीडी क्षमता वाला संयत्र आधा पानी भी नहीं निकाल रहा। दिल्ली में पानी का कुप्रबंधन यहीं नहीं रुकता, 40 फीसद पानी जल बोर्ड की पाइप से रिसाव व 18 फीसद चोरी की वजह से उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता। कितना दुखद है कि दिल्ली में जिस पानी को पीने लायक बनाने में भारी धन और तंत्र लगता है उसका 70 फीसद सिंचाई, वाहनों की सफाई, शौचालय जैसे गैर पेयजल कार्यों में होता है, जबकि एसटीपी से शोधन कर निकला पानी नाले में बहा दिया जाता है। ईमानदारी से गैर पेयजल कार्यों के लिए इस पानी का इस्तेमाल हो तो दिल्ली में आठ से दस घंटे जल आपूर्ति संभव है।

एक बात समझनी होगा कि दिल्ली की आबादी अब तीन करोड़ 40 लाख के करीब पहुंच रही है और इस विशाल जन समुदाय को साल भर पर्याप्त पानी देने के लिए अस्थाई या तदर्थ तरीकों से काम चल नहीं सकता। आज तो दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, लेकिन यह कोई तकनीकी और दूरगामी हल नहीं है। दिल्ली शहर के पास यमुना जैसे सदा नीरा नदी का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। इसके अलावा छह सौ से ज्यादा तालाब हैं जो कि बरसात की कम से कम मात्रा होने पर भी सारे साल महानगर का गला तर रखने में सक्षम हैं।

यदि दिल्ली की सीमा में यमुना की सफाई के साथ–साथ गाद निकाल कर पूरी गहराई मिल जाए। इसमें सभी नाले गंदा पानी छोड़ना बंद कर दें तो महज 30 किलोमीटर नदी, जिसकी गहराई दो मीटर हो तो इसमें इतना निर्मल जल साल भर रह सकता है जिससे दिल्ली के हर घर को पर्याप्त जल मिल सकता है। विदित हो नदी का प्रवाह गर्मी में कम रहता है, लेकिन यदि गहराई होगी तो पानी का स्थाई डेरा रहेगा। दिल्ली में यमुना, गंगा और भूजल से 1900 क्यूसेक पानी प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। इसका 60 फीसद यानी करीब 1100 क्यूसेक सीवरेज का पानी एकत्र होता है। यदि यह पानी शोधित कर यमुना में डाला जाए तो यमुना निर्मल रहेगी और दिल्ली में पेयजल की किल्लत भी दूर होगी। एक बात और दिल्ली में यमुना का पानी अधिक या खतरे के निशान से ऊपर होने की दशा में सराय कालेखां के पास बारापूला, साकेत में खिड़की के पास सात पूला जैसी संरचनाओं को फिर से जीवित कर दिया जाए तो महानगर के कई जलाशय पानीदार हो जाएंगे।

कभी दिल्ली में यमुना के पानी के घटने बढ़ने को नियंत्रित करने वाली नजफगढ़ प्राकृतिक नहर को नाला बना देने और नजफगढ़ – झील को पुनर्जीवित कर दिया जाए तो दिल्ली के पास अपनी क्षमता से दोगुना जल होगा। नजफगढ़ नाला कभी जयपुर के जीतगढ़ से निकल कर अलवर, कोटपुतली, रेवाड़ी व रोहतक होते हुए नजफगढ़ झील व वहां से दिल्ली में यमुना से मिलने वाली साहिबी या रोहिणी नदी हुआ करती थी। यदि इस नाले को फिर नहर में तब्दील कर दें तो दिल्ली को हरियाणा को हर साल कोसना नहीं पड़ेगा। यह केवल पानी की कमी ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की मार के चलते चरम गर्मी, सर्दी और बारिश से जूझने में भी सक्षम हैं। और फिर पानी चाहे जितना भी हो, यदि लीकेज और चोरी नहीं रोकी जाए तो यमुना–तालाब लबालब होने के बाद भी दिल्ली जल के मामले में कंगाल ही रह जाएगी। ❑❑

आरक्षण की चिंगारी बन गई दावानल?

2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय की दुहाई के नाम पर आरक्षण की चिंगारी दावानल की तरह फैल गई है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस के सभी राजनीतिक दल के नेताओं के चुनावी भाषण में मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत बढ़ चढ़कर होने लगी है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एतिहासिक फैसले से 2010 के बाद मुस्लिम समुदाय की 77 केटेगरी 'अन्य पिछड़ी जातियों' के करीब पांच लाख ओबीसी सर्टिफ़िकेट रद्द कर दिए। न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए आरक्षण को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दलों में गहमा–गहमी बनी हुई है और अधिकांश राजनीतिक दल नूरा कुश्ती कर रहे हैं।

आरक्षण की आग में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र दो दशक पहले से ही धधक रहे हैं।

राजनीति से परे आरक्षण व्यवस्था को समझने से ज्ञात होता है कि मूल रूप से भारत में संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था अनुच्छेद 330, 332 और 335 के तहत अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 7.5 प्रतिशत अर्थात कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था ही है। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 10 साल तक फाईलों में धुल खाती रही। 1989 में वी.पी. सिंह ने नेशनल फ्रंट जनता दल के नेतृत्व में राजनीतिक दलों का एक गठबंधन बनाया। एन.टी. रामाराव अध्यक्ष और वीपी सिंह इसके संयोजक थे। 1998 में वीपी सिंह ने भाजपा की मदद से सरकार बनाई और मंडल आयोग की शिफारिशों को लागू करने का निर्णय किया। रिपोर्ट में 'आर्थिक संरचना में असंतुलन को कम करने के लिए अधिक क्षेत्रीय समाधान और योजनाएं बनाने और अधिक से अधिक धनराशि को विकास कार्यक्रमों में निवेश किये जाने की जरूरत पर बल दिया, ताकि उन्नति के क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।'

मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया। तभी से लेकर आज तक आरक्षण की आग अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों में हर राज्य में हर चुनाव के समय किसी न किसी रूप में भड़कती और धधकती है।

विश्व के विकसित देश अमेरिका, चीन और जापान में भी आरक्षण व्यवस्था लागू है। भारत में लंबे समय से चली आ रही "जाति व्यवस्था" देश की आरक्षण नीति स्थापना के लिए जिम्मेदार है।

– डॉ बालाराम परमार 'हँसमुख'

भारत में आरक्षण की शुरुआत ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से मानी जा सकती है। उस समय अमीरों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। लिखित रूप में आरक्षण पर विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने 1882 में मूलतः जाति–आधारित आरक्षण प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया था। 1909 में अंग्रेजों द्वारा जाति और समुदाय के पक्ष में जो आरक्षण शुरू किया वह 1919 में चेंबर फोर्ड की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से आरक्षण के प्रावधान के रूप में सामने आया। 1921 के मद्रास प्रेसिडेंसी के आदेश अनुसार गैर ब्राह्मण के लिए 44 प्रतिशत, ब्राह्मण, मुसलमान, भारतीय एंग्लो–इंडियन के लिए 16–16 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। 1930 में एच.वी. स्टोर कमेटी ने पिछड़ी जातियों को दलित, आदिवासी और पर्वतीय जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया था। तभी से भारतीय समाज विभिन्न वर्गों और समुदायों में विभाजित है।

असल में आरक्षण नामक धधकती आग ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड के 1932–33 के "सांप्रदायिक पुरस्कार" के साथ भारत में निर्यात हुई चिंगारी है। इस पुरस्कार में मुसलमान, सिख, भारतीय इसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। सांप्रदायिक पुरस्कार के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी। इस 'सांप्रदायिक पुरस्कार' के अनुसार "मतदाता को अपने समुदाय के व्यक्ति को ही "मत" देने का प्रावधान था। इस तरह के प्रावधान का गांधी जी ने विरोध और डॉ भीमराव अंबेडकर ने समर्थन किया था। दोनों का गतिरोध पूना पैक्ट के बाद शांत हुआ था। अधिनियम 1935 के तहत दलित वर्ग और आदिम जनजाति नाम की संज्ञा जोड़ी गई।

महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति–जनजाति के साथ मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत और मुसलमान को 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण है।

तमिलनाडु में सबसे अधिक 69 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था है।

संविधान की धारा 15(4) और 16(4) तथा 16(4) 'बी' सरकार को यह अधिकार देती है कि अगर यह साबित हो जाता है कि– 'किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में "उनका" पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है।'

विश्व के विकसित देश अमेरिका, चीन और जापान में भी आरक्षण व्यवस्था लागू है। भारत में लंबे समय से चली आ रही "जाति व्यवस्था" देश की आरक्षण नीति स्थापना के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जाति व्यवस्था में उत्पीड़ित और दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों को पद दलित रखने की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आजादी के पहले और बाद में सभी स्तरों और स्थानों पर जान बुझ कर मानसिकता स्थापित कर रखी है। इसलिए बहुत हद तक शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों में पद दलित समाज के युवाओं को मुख्य धारा में आगे बढ़ने का कारण उचित प्रतीत होता है। आरक्षित वर्ग : अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का दुर्भाग्य है कि चूंकि "वह" आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए "जाति आधारित भेदभाव" स्वीकार करना पड़ रहा है? निचले वर्गों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक और वर्तमानकालीन अन्याय की भरपाई के लिए गारंटी देने के लिए ऐसी जातियों के व्यक्तियों को राज्य एवं संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम में समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और यह संविधान सम्मत है। लेकिन आरक्षण वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में अनारक्षित लोगों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाना अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। जबकि संविधान की मंशा का दायरा तो यहां तक कहता है कि "जाति–धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर दे देना चाहिए। आरक्षण की संकल्पना में यह निहित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जाना मानवीय मूल्य परंपरा का निर्वहन है। आरक्षण का उद्देश्य पूर्वाग्रह रहित समाज का निर्माण करना है। जहां आरक्षण आवश्यक नहीं था, वहां संविधान निर्माता ने बहुत ही सोच समझकर रक्षा सेवा में आरक्षण की अनुपस्थिति इस विश्वास के साथ निहित की, कि सशस्त्र बलों को उच्चतम स्तर पर दक्षता, प्रभावशालीता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की आवश्यकता रखी। राज्यसभा, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के सर्वोच्च पदों को आरक्षण से दूर रखा है। एक चिंतनशील और जवाबदेह नागरिक के नाते बार–बार प्रश्न मन को उद्देलित करता है कि आरक्षण की सामाजिक आग आखिर कहां जाकर रुकेगी? पिछले चार–पांच दशक से आरक्षण के नाम पर बिना सिर पेर के जो आंदोलन हो रहे हैं, उनको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि यह आग कभी नहीं बुझेगी!! क्योंकि संविधान में आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए एक समय सीमा के लिए प्रदान किया गया था। लेकिन आरक्षित पोषित जाति एवं समाज में यह बहुत मजबूत अवधारणा विकसित हो रही है अथवा हो चुकी है कि 'उन्हें' हर हाल में आरक्षण चाहिए ही चाहिए। आरक्षण की जड़ें लगभग हर समाज में फैल गई है। शायद यही कारण है कि हर अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता अपनी ही जाति के लोगों को वोट देते हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई कानून न बने। राजनीतिक दल भी विधानसभा और लोकसभा में बहुमत के चक्कर में राष्ट्रीय हित भूल जाते हैं। क्षेत्रीय दलों का काम ही जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और नस्लवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि उनका गठन ही संकुचित दृष्टिकोंण आधारित हुआ है।

फिर भी एक विश्वास मन में है कि जब भी आरक्षण पोषित जातियां– समाज एवं राजनीतिक दल– आरक्षण से राष्ट्र ने क्या खोया? क्या पाया? का अंतर्मन से विश्लेषण करेंगे तो जरूर 200 साल पहले अंग्रेजों द्वारा निर्यात यह आरक्षण की चिंगारी शैने शैने शिथिल हो जाएगी।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक समरसता एवं धार्मिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत है)

"जैविक उद्यमिताः 37 करोड़ स्टार्टअप का देश" पुस्तक का विमोचन

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के सदस्य, सीबीयू भिवानी पूर्व कुलपति, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजकुमार मित्तल द्वारा लिखित पुस्तक 'जैविक उद्यमिताः 37 करोड़ स्टार्टअप का देश' पुस्तक का विमोचन स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक सीए आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, सह संगठक श्री सतीश कुमार, स्वावलंबी भारत अभियान की सह समन्वयक अर्चना मीना, क्षेत्रीय संयोजक श्री सतीश आचार्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पुस्तक के लेखक डॉ. राजकुमार मित्तल ने बताया कि यह पुस्तक युवाओं के लिए एक ऐसी गाइड बुक है जो उद्यमिता के लिए प्रेरित करती है, उन्हें नए स्टार्टअप करने की प्रेरणा देती है।

उन्होंने कहा, "मैंने यह पुस्तक गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर आईआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को ध्यान में रखकर लिखी है। अगर युवा इसके प्रत्येक अध्याय को पढ़कर उसको फॉलो करता चला गया तो वास्तविकता में वह एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जायेगा। इसके लिए उसे न किसी लोन, न किसी इक्विटी, न किसी बेबुनियादी झंझट में पढ़ने की जरूरत है। वह खुद से एक अच्छा स्टार्टअप कर लेगा। साथ ही युवाओं को इस पुस्तक में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी भी पढ़ने को मिलेगी, जिससे उसे मोटिवेशन एवं सफलता के सूत्र मिलेंगे।"

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कई मुख्य अधिकारी, समाज के प्रमुख लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री/दौसा सांसद श्री जसप्रीत कौर, पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर/स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के निदेशक श्री सतीश चावला, स्वावलंबी भारत अभियान के सह समन्वयक श्री जितेन्द्र गुप्त, डॉ राजीव कुमार, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉ. धर्मेंद्र दुबे, प्रांत समन्वयकगण व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

स्वदेशी जागरण मंच की कार्यशाला व विचार वर्ग सम्पन्न

स्वदेशी जागरण मंच, जयपुर प्रांत की ओर से स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला एवं विचार वर्ग सेवाधाम परिसर सेक्टर–4 जवाहर नगर में आयोजित की गयी। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक एवं जाने–माने आर्थिक चिंतक श्री सतीश कुमार ने भारत@2047 एवं हमारा समय समर्पण विषय पर अपना उद्बोधन दिया। स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक एवं गौतम बुद्ध विश्वविधालय के कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने भी अपनी बात रखी। वर्ग में जयपुर प्रांत के 11 शासकीय जिलों एवं स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े 20 संगठनों के कुल 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें 20 महिला प्रतिनिधि भी शामिल थीं। दो दिन की इस कार्यशाला में कुल 8 सत्रों में भारत 2047 तक कैसे समृद्ध शक्तिशाली बने, के केंद्र बिन्दु के आर्थिक विषयों पर गहन चर्चा व चिंतन मनन किया गया। साथ ही प्रत्यक्ष धरातल पर विषय कैसे उतरे इसकी रूपरेखा बनी।

वर्ग में राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल, स्वदेशी जागरण मंच के राजस्थान क्षेत्र संयोजक श्री सतीश आचार्य, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री धर्मेंद्र दुबे, राजस्थान क्षेत्र के स्वावलंबी भारत अभियान के सम्नव्यक श्री अनिल वर्मा, महिला कार्य प्रमुख मनिशा, जयपुर प्रांत के अभियान संयोजक लोकेंद्र नरुका सहित अनेक वक्ताओं ने जैविक आर्थिक उद्धमिता एवं स्वरोजगार विषय पर अपना उद्बोधन दिया।

https://udaipurkiran.in/workshop-and-thought-class-concluded-by-swadeshi-jagran-manch/

रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में होने लगी बढ़ोतरी

एक बार फिर से रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी शुरू हो गई है जो रोजगार सृजन के लिए अच्छी खबर है। रोजगारपरक सेक्टर की मदद से मई माह में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 9.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं इस अवधि में वस्तुओं के आयात में 7.71 प्रतिशत का इजाफा रहा। चालू वित्त वर्ष 2024–25 में लगातार दूसरे महीने वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।

मई में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फार्मा, केमिकल्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी के साथ चाय, काफी, फल–सब्जी के निर्यात में भी वृद्धि हुई। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष

अश्विनी कुमार ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, यूके, पश्चिम एशिया जैसे देशों से निर्यात आर्डर की बुकिंग में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मई माह में सेवा निर्यात में 15 प्रतिशत का इजाफा रहा। मई में सेवा निर्यात 30.16 अरब डॉलर तो सेवा आयात सिर्फ 17.28 अरब डॉलर का रहा। सेवा निर्यात में व्यापार घाटे की जगह व्यापार बढ़ोतरी से वस्तु निर्यात में होने वाले व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

बढ़ती कीमतों से दाल के आयात में मई में 181 प्रतिशत की बढ़ोतरी। दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इन दिनों दाल का जमकर आयात किया जा रहा है। इस वजह से मई में दाल के आयात में पिछले साल मई के मुकाबले 181.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह में दाल के आयात में 176.53 प्रतिशत का इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ खाद्य तेल के आयात में भी मई माह में 27.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। मई में दाल का आयात 37 करोड़ डॉलर का रहा। दाल आयात में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है।

https://www.jagran.com/business/biz-exports-of-employment-sector-started-increasing-increased-by-9-10-percent-in-may-23739159.html

खुदरा महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत

बीते मई महीने में भारत की खुदरा महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। सालाना आधार पर खुदरा महंगाई 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर आ गई। वहीं, अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई के आंकड़े 4.83 प्रतिशत पर थे। एक साल पहले यानी मई 2023 में यह महंगाई 4.31 प्रतिशत रही थी। खुदरा महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय दायरे के बीच है। रिजर्व इसको चार से छह प्रतिशत के बीच रखना चाह रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट तय की जा रही है।

मई में खाद्य मुद्रास्फीति दर अप्रैल के 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.62 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह मई 2023 में दर्ज 3.3 प्रतिशत से अधिक रही है। ग्रामीण मुद्रास्फीति मई में 5.43 प्रतिशत से घटकर 5.28 प्रतिशत हो गई। वहीं, मई में शहरी मुद्रास्फीति दर 4.15 प्रतिशत थी। भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों के लिए महंगाई दर वार्षिक आधार पर मामूली रूप से कम होकर 27.3 प्रतिशत हो गई।

बीते दिनों एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा– एमपीसी ने इस बात पर गौर किया कि आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है जबकि मुख्य (कोर) मुद्रस्फीति में नरमी (ईंधन और खाद्य पदार्थ की महंगाई को छोड़कर) से खुदरा महंगाई में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ईंधन की महंगाई दर में कमी जारी है। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय है और यह ऊंची बनी हुई है। शक्तिकांत दास के मुताबिक केंद्रीय बैंक खासकर खाद्य महंगाई को लेकर सतर्क बना हुआ है। मौद्रिक नीति निश्चित रूप से महंगाई को काबू में लाने वाली होनी चाहिए और हम टिकाऊ आधार पर इसे 4 प्रतिशत के स्तर पर लाने को प्रतिबद्ध हैं।

https://www.livehindustan.com/business/india-retail-inflation-eases-to-12-month-low-may-data-is-here-201718194981261.html

घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4 प्रतिशत बढ़कर 1.37 करोड़ हुई

मई में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.4 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.37 करोड़ हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा जनवरी–मई 2024 के दौरान घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या 661.42 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 636.07 लाख थी।

आंकड़ों पर गौर करें तो समय पर प्रदर्शन के मामले में अकासा एयर 85.9 प्रतिशत के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद विस्तारा (81.9 प्रतिशत), एआइएक्स कनेक्ट (74. 9 प्रतिशत), इंडिगो (72.8 प्रतिशत), एयर इंडिया (68.4 प्रतिशत) और स्पाइसजेट (60.7 प्रतिशत) हैं। पिछले महीने इडिगो की बाजार हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 61.6 प्रतिशत रही जबकि एयर इंडिया की हिस्सेदारी अप्रैल में 14.2 प्रतिशत से घटकर मई में 13.7 प्रतिशत रह गई।

डीजीसीए ने कहा कि विस्तारा की बाजार हिस्सेदारी 9.2 प्रतिशत रही, लेकिन एआइएक्स कनेक्ट की हिस्सेदारी 5.4 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई। एयर इंडिया, विस्तारा और एआइएक्स कनेक्ट टाटा समूह का हिस्सा हैं। इस बीच अकासा एयर की बाजार हिस्सेदारी अप्रैल में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर मई में 4.8 प्रतिशत हो गई।

https://www.jagran.com/business/biz-domestic-air-passenger-numbers-rise-4-4-per-cent-to-13-7-million-akasa-air-tops-23739149.html

इंश्योरेंस पर अब ग्राहकों को बड़ी राहत

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई – इरडा) ने इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत पॉलिसीहोल्डर्स कुछ शर्तों के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसीहोल्डर इंश्योरेंस की बची हुई अवधि के रिफंड को भी ले सकेंगे। वहीं, इरडा के नए नियम के तहत अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्युमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी।

इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों के बारे में बताया है। इरडा ने कहा– यदि पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी को रद्द कर देता है, तो उसे इसका

कारण बताने की जरूरत नहीं है। ग्राहक पॉलिसी रद्द कर देता है तो बीमाकर्ता को समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी की अवधि एक वर्ष तक है और इस अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है। एक वर्ष से अधिक की अवधि वाली पॉलिसियों के संबंध में समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड प्रीमियम किया जाना चाहिए। सर्कुलर के मुताबिक बीमाकर्ता केवल धोखाधड़ी साबित होने के आधार पर पॉलिसी रद्द कर सकता है। इसके लिए बीमाकर्ता न्यूनतम 7 दिनों का नोटिस दे सकेगा।

इरडा के सर्कुलर में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राहक को एक ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) दिया जाना चाहिए। इसके तहत ग्राहक आसान शब्दों में पॉलिसी के बारे में जान सकेंगे। इसमें बुनियादी विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। इसमें कवरेज का दायरा, ऐड–ऑन, बीमा राशि का आधार, बीमा राशि, विशेष शर्तें और वारंटी, क्लेम प्रक्रिया समेत अन्य जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी।

https://www.livehindustan.com/business/irdai-allows-policyholders-to-cancel-policies-get-refund-big-relief-for-policyholders-201718156733824.html

जुलाई में घट सकते हैं दालों के दाम

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा है कि अच्छे मानसून की उम्मीद और आयात में वृद्धि से अगले महीने से तुअर, चना और उड़द दालों की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से इन तीनों दालों का आयात भी बढ़ेगा। इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

खरे ने संवाददाताओं से कहा, "तुअर, चना और उड़द दालों की कीमतें पिछले छह महीनों से स्थिर हैं, लेकिन उच्च स्तर पर हैं। मूंग और मसूर दालों की कीमत की स्थिति आरामदायक है।" 13 जून को चना दाल का औसत खुदरा मूल्य 87.74 रुपये प्रति किलोग्राम, तुअर (अरहर) 160.75 रुपये प्रति किलोग्राम, उड़द 126.67 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंग 118.9 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर 94.34 रुपये प्रति किलोग्राम था। उपभोक्ता मामले विभाग 550 प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से खुदरा कीमतें एकत्र करता है। खरे ने कहा कि जुलाई से तुअर, उड़द और चना की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने सामान्य मानसून बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

उन्होंने आगे कहा कि हमें अच्छे मानसून, औसत से अधिक बारिश की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि दालों के रकबे में उल्लेखनीय सुधार होगा। बाजार में ऊंची कीमतों को देखते हुए किसान फसलों के रकबे में और बढ़ोतरी करेंगे। बाजार की धारणा में भी सुधार होगा।

सरकार किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। खरे ने जोर देकर कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत चना दाल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने की सरकार की योजना आम आदमी को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।" भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 8 लाख टन तुअर और 6 लाख टन उड़द का आयात किया। म्यांमार और अफ्रीकी देश भारत के प्रमुख निर्यातक हैं।

सचिव ने कहा कि उनका विभाग आयात को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ–साथ घरेलू खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के साथ लगातार संपर्क में है ताकि जमाखोरी न हो। 2023–24 फसल वर्ष (जुलाई–जून) में अरहर का उत्पादन 33.85 लाख टन रहा, जबकि खपत 44–45 लाख टन रहने का अनुमान है। चना का उत्पादन 115.76 लाख टन रहा, जबकि मांग 119 लाख टन है। उड़द के मामले में उत्पादन 23 लाख टन रहा, जबकि खपत 33 लाख टन रहने का अनुमान है। मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

https://www.jagran.com/business/biz-prices-of-tur-chana-urad-dals-likely-to-soften-from-july-on-good-monsoon-higher-imports-says-govt-23739048.html

प्रांतीय विचार वर्ग व कार्यशाला का सफल आयोजन

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत प्रांतीय विचार वर्ग व कार्यशाला का सफल आयोजन दुर्ग ज़िला के अग्रसेन भवन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ अश्वनी महाजन, अखिल भारतीय सह विचार प्रमुख प्रो. राघवेंद्र चंदेल, मध्य क्षेत्र संयोजक श्री सुधीर दाते जी व मध्य क्षेत्र संगठक श्री केशव दुबौलिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में स्वदेशी और स्वावलंबन से संबंधित 11 विषयों पर सत्रों का नियोजन किया गया। इस आयोजन में 16 ज़िलों के 145 प्रांतीय और जिला स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जिसमें महिलाओं की सहभागिता 50 प्रतिशत रही। स्वदेशी की विकास यात्रा से स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत वर्तमान चुनीतियों और उससे निपटने पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ प्रांत के संयोजक श्री जगदीश पटेल ने स्वावलंबी भारत की यात्रा पर अपनी बात रखते हुए आगामी स्वदेशी मेलों और उनके क्रियान्वन का विषय रखा। ❑❑

स्वदेशी गतिविधियां

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम

बैठकें

सचित्र झलक

स्वाई माधोपुर, राजस्थान

अभियान बैठक, गुवाहटी, असम

प्रांतीय विचार वर्ग, मालवा प्रांत

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जून 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

बैठकें

सचित्र झलक

गोलपारा, असम

सिंधूदुर्ग, कोकण

इम्फाल, मणिपुर

बुलढ़ाणा, महाराष्ट्र

मोहाली, पंजाब

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती